घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 300- बुधवार 02- सितम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

शंघाई सहयोग संगठन समिट में पीएम मोदी का सख्त संदेश....आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना होगा,दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं

बिश्केक,01 सितंबर 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक और एकजुट कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा कि आतंकवाद के वित्तपोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और आतंकियों को सुरक्षित पनाह देने वाले पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त करना होगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं हो सकती और जो देश आतंकवाद को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, उन्हें स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए कि आतंकवाद किसी के लिए रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता।

प्रधानमंत्री ने एससीओ के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित 26वें शिखर सम्मेलन में कहा कि पिछले 25 वर्षों में संगठन ने यूरेशिया के विशाल भूभाग में संवाद और सहयोग की मजबूत परंपरा विकसित की है तथा मानवता के विकास और अपने लोगों की भलाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब अगले 25 वर्षों में इस सहयोग को ठोस परिणामों में बदलना एससीओ का लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जब दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, साझा भूगोल को साझा अवसरों में बदलने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है। मोदी ने एससीओ के संदर्भ में भारत की सोच के तीन स्तंभों- सुरक्षा, संपर्क और अवसर का उल्लेख करते हुए कहा कि अब इन तीनों स्तंभों को दृष्टिकोण से आगे बढ़ाकर ठोस परिणामों में बदलने का समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति और सुरक्षा इस दिशा में पहली आवश्यकता है। आतंकवाद आज भी पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। इसके खिलाफ लड़ाई को केवल कार्रवाई-प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रखा जा सकता। आतंकवाद के वित्तपोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को खत्म करना होगा। जो देश आतंकवाद को अपनी नीति का साधन बनाते हैं और आतंकियों को पनाह तथा समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए। मोदी ने कहा कि शांत और सुरक्षित यूरेशिया की साझा आकांक्षा अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता से भी जुड़ी है। भारत अफगानिस्तान के लोगों के विकास और मानवीय सहायता में योगदान देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में सुरक्षा की परिधि और व्यापक हो गई है। पश्चिम एशिया के संकट ने दिखाया है कि किसी एक क्षेत्र का संघर्ष वहीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ता है। इसका सबसे अधिक खामियाजा ग्लोबल साउथ के देशों को भुगतना पड़ता है।

उन्होंने दोहराया कि सभी तनावों और युद्धों का समाधान युद्धक्षेत्र में नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति के जरिए ही संभव है। मोदी ने ड्रग तस्करी को केवल अपराध नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने एससीओ के तहत सुरक्षा खतरों, संगठित अपराध, सूचना सुरक्षा और मादक पदार्थों जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए स्थापित किए जा रहे केंद्रों का स्वागत किया और कहा कि इन्हें व्यावहारिक समन्वय तथा समय पर कार्रवाई का प्रभावी माध्यम बनाया जाना चाहिए। एससीओ के दूसरे स्तंभ कनेक्टिविटी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं।

पीएम मोदी ने एससीओ को लेकर भारत की सोच जाहिर की

प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ को लेकर भारत की सोच जाहिर की। उन्होंने कहा, 'आज जब विश्व अनिश्चितता और अस्थिरता से गुजर रहा है, हमें अपने साझा भूगोल को साझा अवसरों में बदलना है और हमारे प्रयासों से हमारे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना हैं। पिछली बैठक में मैंने एससीओ को लेकर भारत की सोच के तीन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया था: एस से सिक्योरिटी (सुरक्षा), सी से कनेक्टिविटी और ओ से ऑपर्चुनिटी (अवसर)। अब समय है कि इन तीनों स्तंभों को विजन से आगे बढ़ाकर ठोस आउटकम (उपलब्धि) तक ले जाया जाए। और इसकी पहली आवश्यकता है–शांति और सुरक्षा। आतंकवाद आज भी पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। इसके विरुद्ध लड़ाई में हम एक्शन-रिएक्शन की सोच तक सीमित नहीं रह सकते। '

पीएम मोदी ने एक-दूसरे से जुड़े रहने को दुनिया के लिए जरूरी बताया

प्रधानमंत्री मोदी ने एक-दूसरे से जुड़े रहने को दुनिया के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा,' आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में सुरक्षा की परिधि और भी व्यापक हो चुकी है। पश्चिम एशिया के संकट ने यह दिखाया है कि किसी एक क्षेत्र का संघर्ष वहीं तक सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव पूरे विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी,मैरीटाइम ट्रेड और सप्लाई चेन्स पर पड़ता है। इसका सबसे अधिक खामियाजा ग्लोबल साउथ के देशों को भुगतना पड़ता है। इसलिए भारत का आह्वान रहा है कि सभी तनावों और युद्धों का समाधान बैटलफील्ड पर नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है।

पुतिन बोले...शंघाई सहयोग संगठन अब दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन की शुरुआत कुछ देशों के छोटे संगठन के तौर पर हुई थी, लेकिन अब यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन बन गया है। पुतिन के मुताबिक, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में दुनिया की करीब आधी आबादी रहती है और ये देश दुनिया की कुल जीडीपी के करीब एक-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

संक्षिप्त समाचार

कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा घरेलू रसोई गैस के दाम स्थिर

नई दिल्ली,01 सितम्बर 2026। सरकारी तेल कंपनियों ने महीने की शुरुआत में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। अलग-अलग शकमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा, घरेलू रसोई गैस के दाम स्थिर नई दिल्ली, 1 सितंबर। सरकारी तेल कंपनियों ने महीने की शुरुआत में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। अलग-अलग शहरों में इसकी कीमत 9.50 से 12 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ी है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 2,747.50 रुपए, मुंबई में 2,701 रुपए, कोलकाता में 2,884 रुपए और चेन्नई में 2,916.50 रुपए में मिलेगा। कमर्शियल गैस के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और कैटरिंग कारोबार से जुड़े लोगों पर अतिरिक्त खर्च का असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है। हरों में इसकी कीमत 9.50 से 12 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ी है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 2,747.50 रुपए, मुंबई में 2,701 रुपए, कोलकाता में 2,884 रुपए और चेन्नई में 2,916.50 रुपए में मिलेगा। कमर्शियल गैस के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और कैटरिंग कारोबार से जुड़े लोगों पर अतिरिक्त खर्च का असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है।

पांच राज्यों के कृषि विकास के लिए 1283 करोड़ जारी..शिवराज बोले... किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़

नई दिल्ली,01 सितंबर 2026। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान हमारे देश की आत्मा और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 'टीम इंडिया' के रूप में काम कर रही हैं ताकि हर खेत तक पानी, उन्नत बीज, यंत्रीकरण और आधुनिक डिजिटल सुविधाएं पहुंच सकें। केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर और समृद्ध किसान' के विजन को धरातल पर तेजी से उतारने के अभियान के अंतर्गत मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पांच राज्यों- उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और त्रिपुरा के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। कृषि मंत्री ने सरकार के किसान कल्याण संकल्प के तहत 5 राज्यों को कृषि विकास के लिए 1,283 करोड़ रुपये से अधिक की दूसरी 'मदर सैंक्शन' जारी करने के साथ पीएम-आरकेवीवाई और कृषोन्नति योजनाः आधुनिक खेती और किसानों के सशक्तीकरण को नई गति देने के तहत इन राज्यों के लिए 1283.11 करोड़ रुपये धनराशि भी स्वीकृत की। उन्होंने कहा कि किसान हमारे देश की आत्मा और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर 'टीम इंडिया' के रूप में काम कर रही हैं ताकि हर खेत तक पानी, उन्नत बीज, यंत्रीकरण और आधुनिक डिजिटल सुविधाएं पहुंच सकें। उन्होंने राज्यों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन और फंड के सदुपयोग पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के हित में किसी भी संसाधन या वित्तीय मदद की कमी नहीं आने दी जाएगी। बैठक में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव अतीश चंद्रा सहित संबंधित राज्यों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर प्रोटेस्ट की सभी एफआईआर रद्द कीं, नई एफआईआर भी अब दर्ज नहीं होंगी....

कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर का मार्च वापस लिया

नई दिल्ली,01 सितम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से जुड़ी सभी एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह आदेश देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज मामलों पर लागू होगा। कोर्ट ने साफ किया कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है, उन पर केस चलता रहेगा। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर के मार्च को वापस ले लिया है। ये एफआईआर 20 से 25 जुलाई के बीच जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद दर्ज की गई थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत लिया

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर रद्द करने

का फैसला सिर्फ इसी मामले के खास तथ्यों और हालात को देखकर लिया गया है, इसलिए इसे दूसरे मामलों के लिए उदाहरण और बाध्यकारी फैसला नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के तहत मिली अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल इस शर्त पर किया जा रहा है कि दोनों पक्ष कोर्ट के सामने हुए समझौते का पूरी तरह पालन करेंगे।

सीजेआई सूर्यकांत ने सौरव दास की तारीफ की,कहा...आपने अच्छा कदम उठाया : लाइव लॉ के अनुसार रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट रूम में सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास भी मौजूद थे। वे बेंच के सामने पेश हुए और ग्रुप की तरफ से एक बयान पढ़ा-'मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के भरोसे पर आज लगी अदालती मुहर और ऑर्डर को देखते हुए हम 5 सितंबर का मार्च वापस ले रहे हैं। ' सौरव के बयान के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- 'आपने भी बहुत अच्छा कदम उठाया है। एक संस्था के रूप में, हम आभारी हैं कि ऐसा सकारात्मक वातावरण बनाया गया है जो युवाओं के लिए मददगार होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, 'अगस्त की शुरुआत में सरकार के डेलिगेशन ने हमसे बात करना बंद कर दिया था, फिर हमें लगा कि ये विश्वासघात करना चाहते हैं, इसलिए हमने 5 सितंबर को मार्च निकालेंगे का फैसला किया।

खड़गे ने चुनाव आयोग को बीजेपी बचाओ कमीशन कहा..बोले...जहां बीजेपी को फायदा होता है,वहां मतदाता जोड़ दिए जाते हैं

नई दिल्ली,01 सितम्बर 2026। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आयोग निष्पक्ष चुनावों के संरक्षक की जगह 'सेव बीजेपी चेयर कमीशन' की तरह काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी 'वोट चोरी' के जरिए भारत के लोकतंत्र को खोखला करने की साजिश कर रही है। यह साजिश अब सामने आ गई है और लोग वोटों की चोरी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। खड़गे ने हिंदी में किए एक्स पोस्ट में आरोप लगाया कि बीजेपी की 'वोट चोरी' के जरिए भारतीय लोकतंत्र को खोखला करने की साजिश सामने आ रही है। जहां बीजेपी को फायदा होता है, वहां मतदाता जोड़े जाते हैं और जहां फायदा नहीं होता, वहां वोट बांट दिए जाते हैं। ' खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच अचानक 39 लाख मतदाता बढ़ गए थे। अब एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ड्राफ्ट सूची से 2.07 करोड़ मतदाता बाहर हैं। उन्होंने सवाल किया- क्या बीजेपी को जिताने के लिए चुनावों के दौरान इन मतदाताओं के नाम हटाए गए? खड़गे ने कहा कि बंगाल में एसआईआर के दौरान हटाए गए नामों में से 91% नाम अपील के बाद फिर से जोड़ने पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि यही खेल दिल्ली में भी दोहराया जा रहा है।

नेपाल में फिर बाढ़ का अलर्ट : नदियों का जलस्तर बढ़ा..मौत का आंकड़ा 1 हजार के पार हुआ,सबसे ज्यादा चितवन में 321 शव बरामद

काठमांडू,01 सितम्बर 2026। नेपाल में नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद 7 जिलों में बाढ़ का नया अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, तनहूं, नवलपरासी और चितवन जिलों में नदियों के किनारे बसे इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है। 26 अगस्त को तिब्बत में ग्लेशियर टूटने के बाद नेपाल के कई इलाकों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ। इस आपदा में मौत का आंकड़ा 1 हजार के पार हो चुका है। नेपाल में 1066 और तिब्बत में 16 लोगों की मौत हुई है। चितवन में अब तक सबसे ज्यादा 321 शव बरामद हुए हैं। जबकी 4400 से ज्यादा लोग लापता हैं। चीन नेपाल में डीएनए जांच करने वाले विशेषज्ञों की टीम भेजेगा। इसका मकसद बाढ़ में मारे गए उन

लोगों की पहचान करने में मदद करना है, जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। चीन नेपाल को डीएनए जांच के उपकरण, ड्रोन और पानी साफ करने के उपकरण समेत जरूरी सामान भी भेजेगा। नेपाल बाढ़ में 5 साल की मनीषा 60 घंटे तक मलबे के नीचे फंसी रही। रेस्क्यू टीम ने उसे रसुवा जिले में जिंदा निकाला। होश में आने पर उसने अपने माता-पिता से पूछा, 'आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए?

रेलवे सुरक्षा और माल ढुलाई क्षमता को मिलेगी मजबूती, तीन अहम परियोजनाओं को मंजूरी

नई दिल्ली,01 सितंबर 2026। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा, सिग्नलिंग आधुनिकीकरण और माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। समस्तीपुर मंडल के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपये, दक्षिण पूर्व रेलवे में अद्रा-जॉयचंडीपहाड़-सांका बाईपास लाइन के लिए 272 करोड़ रुपये और मुरादाबाद मंडल में 712 रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 के लिए 170 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं पर कुल 675 करोड़ रुपये खर्च होंगे। रेलवे ने कहा है कि इनके जरिए पुराने सिग्नलिंग तंत्र का आधुनिकीकरण, ट्रेन परिचालन की सुरक्षा में वृद्धि, मालगाड़ियों की आवाजाही में तेजी

और रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। मंत्रालय के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के 21 स्टेशनों पर मौजूदा पैनल इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की मंजूरी दी गई है।

इस कार्य पर 233 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कंप्यूटर आधारित यह आधुनिक प्रणाली पुराने रिले आधारित तंत्र की तुलना में अधिक विश्वसनीय होगी। इससे खराबी की पहचान और रखरखाव आसान होगा तथा परिचालन में लचीलापन बढ़ेगा। परियोजना से इन स्टेशनों पर सिग्नलिंग व्यवस्था मजबूत होगी और कवच प्रणाली लागू करने के लिए आवश्यक आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे में अद्रा छोर से जॉयचंडीपहाड़ के बीच 11 किलोमीटर लंबी बाईपास लाइन बनाने को 272 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। अद्रा-जॉयचंडीपहाड़-सांका बाईपास से मौजूदा परिचालन बाधाएं और सतही क्रॉसिंग के कारण होने वाली देरी कम होगी।

बाईपास आगामी तीसरी लाइन से द्विदिशीय संपर्क उपलब्ध कराएगा और मालगाड़ियों के लिए अलग मार्ग सुनिश्चित करेगा। परियोजना से प्रतिदिन अनुमानित 6.065 मालगाड़ियों की आवाजाही को सुविधा मिलेगी। इसके पूरा होने पर अतिरिक्त 8.88 एमटीपीए माल यातायात संभालने की क्षमता विकसित होने की उम्मीद है।

मोदी की फिर अपील : जरूरत न हो तो सोना नहीं खरीदे,वैश्विक संकट में भारत की जीडीपी 7.8 प्रतिशत दर से बढ़ी...यह देशवासियों की मेहनत का नतीजा...

नई दिल्ली,01 सितम्बर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रहने पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि यह उपलब्धि देशवासियों की इच्छाशक्ति, मेहनत और सामूहिक ताकत का नतीजा है। पीएम ने एक बार फिर लोगों से गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपील की। उन्होंने कहा, 'अगर जरूरत न हो तो सोना नहीं खरीदना चाहिए।' इससे पहले 11 मई को भी पीएम ने देशवासियों से सोना नहीं खरीदने

की अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा- देश के अंदर कुछ लोग निराशा फैलाने और 'झूठ की गूंज' के सहारे माहौल खराब करने में लगे हैं। इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। देश को यही रफ्तार बनाए रखनी होगी और आगे भी तेजी से विकास करना होगा। उन्होंने कहा, विदेश में घूमने के लिए यात्राएं करने और विदेश में शादी करने से बचना चाहिए। लोगों को मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पीएम ने यह भी कहा, जितना ज्यादा स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाएगा, भारत उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब देश की युवा पीढ़ी को एक विकसित भारत सौंपा जाएगा।

जीडीपी दर 7.8 प्रतिशत को लेकर भाजपा का राहुल गांधी पर वार कहा-उन्हें देश को गुमराह करने के लिए माफी मांगनी चाहिए...

चालू वित वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़ों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.8 प्रतिशत रहने पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आज कहा कि दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताने के लिएकांग्रेस नेता को अपनी गलतबयानी पर देश से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा ने कहा कि वैश्विक संकट और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत की मजबूत आर्थिक विकास दर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सरकार की आर्थिक नीतियों का नतीजा है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पार्टी के मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन ने कहा कि जिस तिमाही में खाड़ी संकट, तेल आपूर्ति की चुनौतियां और वैश्विक अनिश्चितता बनी रही।

संपादकीय

आर्थिकी के अच्छे दिन

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहना इसलिए सुखद आश्चर्य का विषय है,क्योंकि ऐसे आंकड़े वैश्विक उथल-पुथल और विशेष रूप से ऊर्जा उत्पादों की ऊंची कीमतों के बाद भी सामने आए। अनेक अर्थशास्त्री ऐसी आशा नहीं कर रहे थे। इसलिए और भी, क्योंकि पिछले साल इसी तिमाही में अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.9 प्रतिशत रही थी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य चुनौती भरा दिखाई दे रहा था।

इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहने का एक बड़ा कारण घरेलू मांग कायम रहना है। इसके अलावा सरकारी कैपिटल खर्च,मैन्यूफैक्चरिंग,कंस्ट्रक्शन और एक्सपोर्ट ने भी जीडीपी वृद्धि में योगदान दिया। यह स्वाभाविक है कि जीडीपी के उम्मीद से अच्छे आंकड़ों पर प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की और इन्हें निराशावादियों के लिए झटका बताया। यह स्पष्ट है कि उनका संकेत उनकी ओर था,जो कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बताए जाने के खीझ भरे दावे का समर्थन कर रहे थे।

जीडीपी के आकर्षक आंकड़े यह भी रेखांकित कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका से व्यापार समझौता न हो पाने के बाद भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। चूंकि इसमें उन व्यापार समझौतों का योगदान रहा, जो पिछले कुछ समय में कई देशों के साथ हुए,इसलिए ऐसे समझौतों का सिलसिला कायम रहना चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था को बल देने के साथ अमेरिका के दबाव का प्रतिकार करने में भी सफलता मिलेगी।

7.8 प्रतिशत विकास दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर सबसे तेज बढ़ती आर्थिकी बनी,लेकिन भारत को इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। विकास दर बढ़ने के साथ ही भारतीय नागरिकों की औसत आय बढ़ना भी आवश्यक है। इसके लिए भारत का लक्ष्य आठ प्रतिशत से अधिक विकास दर हासिल करना होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए, क्योंकि एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था इस लक्ष्य को पाने की क्षमता रखती है और दूसरे ऐसी विकास दर ही देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को आसान बना सकती है। इससे ही निर्धनता को दूर करने के उपायों को बल देने में सफलता मिलेगी।

अब जब यह स्पष्ट है कि मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ ने जीडीपी को सहारा देने का काम किया,तब फिर इस सेक्टर की क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। मैन्यूफैक्चरिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने भी जीडीपी को बल दिया। सबसे ज्यादा लोगों को काम देने वाला यह सेक्टर और फले-फूले, लेकिन गुणवत्ता के मानकों पर खरा उतरते हुए। यह देखने की जिम्मेदारी नीति-नियंताओं की है। उन्हें इसके प्रति भी सतर्क रहना होगा कि कमजोर मानसून अगली तिमाही की विकास दर को प्रभावित न करने पाए।

22 हजार करोड़ का दावा,6.5 करोड़ का निपटारा:आखिर किस कीमत पर?

डॉ .प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा सुभाष चंद्र बैंक के लगभग 22,006 करोड़ रुपये के दावों के निपटारे को मात्र 6.5 करोड़ रुपये में अस्थायी मंजूरी देने के आदेश ने बैंकिंग क्षेत्र को झकझोर दिया है और दिवालियापन कानून तथा देश के आर्थिक न्याय को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। यह टकराव केवल व्यावसायिक संघर्ष नहीं है,बल्कि बड़े कॉरपोरेट समूहों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों,नियामक संस्थानों और न्यायपालिका की व्यवस्था के लिए एक चुनौती है,जो एक ही मंच पर खड़े दिखाई देते हैं। जब इतने बड़े ऋण की वसूली के लिए 99.97 प्रतिशत तक की कटौती की जाती है,तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कानून निष्पक्ष होगा,या कम से कम आर्थिक शक्ति के अनुरूप कानून की व्याख्या अपरिवर्तित रहेगी। इसलिए,इस निर्णय ने जनता की नाराजगी,राजनीतिक बहस और संस्थानों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दिवालियापन और दिवालिया संहिता मूल रूप से संकटग्रस्त कंपनियों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पुनर्जीवित करने,लेनदारों के हितों की रक्षा करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। हालांकि,यदि कोई समाधान योजना इतनी कठोर प्रतीत होती है कि अधिकांश दावे को छोड़ दिया जाता है,तो समाधान प्रक्रिया की वास्तविक प्रकृति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। किसी कानून की वैधता केवल यह नहीं है कि वह कानूनी रूप से एक प्रक्रिया स्थापित कर सकता है,बल्कि यह उचित और जनहित के अनुरूप भी होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के धन में भारी कमी-जो अंततः नागरिकों की जमा राशि और करों द्वारा समर्थित है - प्रणाली की जवाबदेही को प्रभावित करेगी। इससे यह धारणा बनती है कि उधारकर्ता का सामाजिक वर्ग,राजनीतिक संबंध और व्यावसायिक शक्ति वसूली की समय-सारणी और उसकी गंभीरता को प्रभावित कर सकती है।

यह एक संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि भारत में बैंकिंग प्रणाली छोटे कर्जदारों के प्रति बेहद कठोर मानी जाती है। किसान, छोटे व्यापारी,निम्न मध्यम वर्ग के वेतनभोगी और शिक्षा ऋण लेने वाले छात्रों को मामूली चूक पर भी अक्सर नोटिस,वसूली की कार्रवाई और दंड का दबाव झेलना पड़ता है। इसके विपरीत, जब बड़े व्यावसायिक ऋणों की बात आती है,तो पुनर्गठन, समाधान और कटौती जैसे तकनीकी शब्द आम नागरिक को यह नहीं समझा पाते कि नुकसान किसका होगा। ₹22,000 करोड़ की बड़ी रियायत से असमानता पैदा होना तय है,जब एक किसान की जमीन ₹50,000 के बकाया ऋण के कारण खतरे में पड़ जाती है। यह असमानता न केवल आर्थिक है, बल्कि नैतिक भी है,जो राज्य और उसकी संस्थाओं में नागरिकों के विश्वास को प्रभावित करती है।

इस मुद्दे का एक और पहलू भारत की कॉर्पोरेट ऋण वसूली व्यवस्था की अपारदर्शिता है। दावे की वास्तविक राशि, स्वीकृत प्रतिशत, कटौती के निर्धारण में प्रयुक्त प्रक्रिया और संबंधित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन का आधार आम नागरिक के लिए समझना कठिन है। जब दस्तावेज़,मूल्यांकन और निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल भाषा में उपलब्ध न हों और सार्वजनिक जांच के लिए खुले न हों,तो ऐसे मामलों में संदेह होना स्वाभाविक है। यह संदेह तब और भी प्रबल हो जाता है जब कोई निर्णय ऐसे समय में आता है जब सरकार और बड़े उद्योगपतियों के बीच किसी प्रकार का संबंध है या नहीं, इस पर राजनीतिक बहस चल रही होती है। इसलिए यह केवल एक व्यक्ति या एक कंपनी का मामला नहीं है, बल्कि यह वित्तीय न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता का प्रश्न है।

समर्थकों के बीच यह बहस हो सकती है कि दिवालियापन व्यवस्था का लक्ष्य हमेशा अधिकतम वसूली नहीं बल्कि एक व्यावहारिक समाधान होना चाहिए। किसी व्यवसाय का परिसमापन संपत्ति मूल्यों में गिरावट के कारण हो सकता है और मुकदमेबाजी जारी रखने से बैंकिंग प्रणाली को अल्पकालिक लाभ न हो, ऐसे में कम राशि का समझौता भी एक प्रशासनिक समाधान के रूप में देखा जा सकता है। यह तर्क पूरी तरह से निराधार नहीं है। लेकिन ऐसे सभी कारणों की निष्पक्षता,निरंतरता और समान परिस्थितियों में समाधान की प्रयोज्यता के संदर्भ में गहन जांच की जानी चाहिए। यदि महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उधारकर्ताओं के साथ बेहतर व्यवहार किया जाता है और छोटे उधारकर्ताओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो प्रक्रिया की वैधता कमजोर हो जाती है। यहीं पर यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि कानूनी रूप से वैध और सामाजिक रूप से न्यायसंगत में क्या अंतर है।

इस प्रकरण ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे को भी छुआ हैः क्या भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग संस्कृति वास्तव में सुधार की ओर अग्रसर हुई है या यह अभी भी राजनीतिक और आर्थिक दबावों के प्रति संवेदनशील है? यदि बैंक बड़े जोखिम भरे ऋण देते हैं,तो चूक के कारण होने वाले नुकसान का अंतिम बोझ सरकारी खजाने पर ही पड़ेगा और निजी लाभ, सार्वजनिक हानि का पुराना रूप फिर से दोहराया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में, बैंकिंग सुधार की मांगें सतही प्रतीत होती हैं। चार चरणों में जवाबदेही की आवश्यकता हैः ऋण स्वीकृति,निगरानी, चूक और समाधान। यदि किसी समस्या का अंतिम समय में बड़े पैमाने पर छंटनी करके समाधान किया जाता है, तो पिछली चूकों और प्रणालीगत विफलताओं को छुपाना संभव नहीं है।

यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी भी है। चुनाव ही लोकतंत्र का एकमात्र साधन नहीं हैं,और इसकी वैधता इस बात पर टिकी है कि नागरिकों को न्याय के निष्पक्ष कार्यान्वयन पर भरोसा हो। लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास तब कम हो जाता है जब आम नागरिकों को लगता है कि कानून शक्तिशाली लोगों का पक्ष लेते हैं और कमजोरों को दंडित करते हैं। इसलिए,इस विवाद में केवल राजनीतिक बयान देना पर्याप्त नहीं है। एक संस्थागत समीक्षा की आवश्यकता है जो यह दर्शा सके कि समाधान योजना किन मानदंडों पर आधारित थी,किन नियमों का पालन किया गया और क्या जनता के हितों की रक्षा की गई।

सुभाष चंद्र के मामले में, यह एक विशिष्ट व्यवसायी की कहानी बनकर उभरी है। यह भारत की वित्तीय अखंडता का मुद्दा बन गया है। यह इस बात की याद दिलाता है कि आर्थिक सुधारों को केवल निवेश,पुनर्गठन या व्यापार करने में सुगमता के आधार पर नहीं मापा जाना चाहिए,बल्कि इस आधार पर भी मापा जाना चाहिए कि वे विश्वास,समानता और न्याय को कितना बढ़ावा देते हैं। जब बैंकिंग और दिवालियापन प्रणाली शक्तिशाली उधारकर्ताओं की कठिनाइयों को कम करने और कमजोर उधारकर्ताओं को दंडित करने का साधन बन जाती है, तो यह सुधार नहीं बल्कि असंतुलन का संस्थागतकरण होता है। जब ऐसा समय आता है,तो यह मायने नहीं रखता कि कितना ऋण माफ किया गया,बल्कि यह मायने रखता है कि इस माफी से किसे, क्यों और किस कीमत पर लाभ हुआ।

मर रहा सूचना का अधिकार, निष्क्रिय हो देख रही है सरकार

-डॉ. शैलेश शुक्ला,लखनऊ,उत्तर प्रदेश

सूचना का अधिकार आज खुद ही सांस के लिए संघर्ष कर रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। जो कानून आम आदमी को अफसर से सवाल पूछने की ताकत देता था,वह आज खुद अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहा है। आंकड़े डराने वाले हैं। देश में उनतीस सूचना आयोग हैं, एक केंद्रीय और अट्ठाईस राज्यों के। जून, 2025 तक इन सभी में कुल चार लाख तेरह हजार नौ सौ बहत्तर अपील और शिकायतें पेंडिंग थीं। केंद्रीय सूचना आयोग की ही बात करें तो एक फरवरी,2026 में सरकार ने राज्यसभा में बताया कि वहां उनतीस हजार चौंतीस अपील और तीन हजार पांच सौ सतहत्तर शिकायतें यानी कुल बत्तीस हजार छह सौ ग्यारह मामले लंबित हैं। अगस्त, 2026 में यह संख्या चालीस हजार पार कर गई, जब छत्तीस हजार तीन सौ पचास अपील और तीन हजार सात सौ तैंतीस शिकायतें पोर्टल पर दिखीं। इसका सीधा अर्थ है कि जिस व्यक्ति ने गांव के हैंडपंप,राशन कार्ड या छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी मांगी, उसकी दूसरी अपील की सुनवाई दो साल बाद होगी। तब तक अधिकारी रिटायर हो चुका होगा और सवाल बेमानी हो जाएगा।

यह भीड़ मामलों की अधिकता से नहीं,कुर्सियां खाली रखने से बनी है। सरकार की सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी नियुक्तियां न करना है। अक्टूबर,2025 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि केंद्रीय सूचना आयोग में चीफ का पद 14 सितंबर,2025 से खाली है और दस में से आठ आयुक्तों के पद खाली हैं। दस में से आठ कुर्सियां खाली हों तो काम कैसे चलेगा। राज्यों में स्थिति और खराब है। जुलाई, 2024 से अक्टूबर,2025 के बीच 29 में से छह आयोग अलग अलग अवधि में पूरी तरह बंद रहे क्योंकि वहां कोई आयुक्त ही नहीं था। हिमाचल प्रदेश और झारखंड अक्टूबर,2025 तक बंद थे। जब आयोग ही बंद रहेगा तो नागरिक कहां जाएगा। दूसरी वजह है पुरानी कार्यपद्धति। एक आयुक्त साल में औसतन अट्ठाईस सौ मामलों का निपटारा करता है,जबकि हर साल 30,000 से ज्यादा नए मामले आ जाते हैं। एक गड्ढा भरते ही दो नए खुद जाते हैं। इस गति से पेंडेंसी कभी खत्म नहीं होगी। कई राज्यों में सुनवाई में दो साल लग रहे हैं।

तीसरी वजह सबसे गंभीर है और वह है सरकार की मंशा। आरटीआई कानून की धारा चार एक बी में लिखा है कि हर विभाग को 17 तरह की जानकारी खुद ही वेबसाइट पर डालनी होगी। बजट,वेतन,विदेश यात्रा, सरकारी गाड़ी,बंगला,ठेके,सब्सिडी के लाभार्थी, सब कुछ। इसे स्वतः प्रकटीकरण कहते हैं। सोच यह थी कि जानकारी पहले से सार्वजनिक होगी तो आरटीआई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हकीकत में अस्सी फीसदी से ज्यादा विभाग इसका पालन नहीं करते। वेबसाइट पर दस साल पुराना डेटा पड़ा है या कुछ है ही नहीं। नतीजा एक ही सवाल पर हजारों आरटीआई आती हैं और आयोग दब जाता है। यह बोझ सरकार ने खुद बनाया है।चार लाख से अधिक पेंडिंग मामले सिर्फ फाइल नहीं, चार लाख लोगों के टूटे भरोसे की कहानी हैं। इसी कानून से आदर्श सोसाइटी, कॉमनवेल्थ,टू जी जैसे घोटाले उजागर हुए। इसी से गरीब की पेंशन, छात्र की कॉपी, किसान का मुआवजा जैसे सवालों के जवाब मिले।

दुनिया जब बुरे दौर में है तब भारत के आर्थिक उजाले

ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

दुनिया आज जिस दौर से गुजर रही है,वह आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टियों से असाधारण चुनौतियों का दौर है। रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव,पश्चिम एशिया में तनाव,अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा,वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने कठिन प्रश्न खड़े कर दिए हैं। ऐसे समय में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस मजबूती का परिचय दिया है,वह केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं,बल्कि बदलते भारत की सामर्थ्य का प्रमाण है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8 प्रतिशत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत को ऐसी उम्मीद के रूप में प्रस्तुत किया है,जिसकी ओर दुनिया आश्चर्य और विश्वास दोनों के साथ देख रही है। इस विकास दर ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक शक्ति और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी है एवं एक उजाला बिखेरा है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वृद्धि ऐसे समय दर्ज हुई है,जब परिस्थितियां सामान्य नहीं थीं। महंगाई,ऊर्जा संकट, भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पथ मजबूत बना रहा। पिछले वर्ष इसी तिमाही में विकास दर 6.9 प्रतिशत थी। यानी एक वर्ष में आर्थिक वृद्धि की गति में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया है। घरेलू मांग की मजबूती, सरकारी पूंजीगत व्यय, विनिर्माण, निर्माण और निर्यात जैसे क्षेत्रों का योगदान इस प्रदर्शन के पीछे महत्वपूर्ण रहा है।

आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ तभी समझ में आता है,जब उसे उसके वैश्विक संदर्भ में देखा जाए। आज दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं केवल आर्थिक नीतियों से प्रभावित नहीं हो रहीं,बल्कि युद्ध, कूटनीतिक तनाव,ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक संबंध भी उनकी दिशा तय कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक एवं रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पश्चिम एशिया का तनाव ऊर्जा बाजार और वैश्विक आपूर्ति तंत्र के लिए चिंता पैदा करता है। इन परिस्थितियों में भारत का अपेक्षाकृत तेज आर्थिक विकास यह संकेत देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने लिए ऐसे मजबूत घरेलू आधार तैयार किए हैं,जो बाहरी झटकों को सहने की क्षमता रखते हैं। यही वह परिवर्तन है जो भारत को केवल एक बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं,बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे ले जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल घरेलू बाजार है। करोड़ों उपभोक्ताओं की मांग, बढ़ता मध्यम वर्ग, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, बुनियादी ढांचे पर निवेश और बदलती उपभोग संस्कृति ने अर्थव्यवस्था को आंतरिक गति प्रदान की है। जब वैश्विक बाजार अनिश्चित हों, तब घरेलू मांग अर्थव्यवस्था के लिए सुरक्षा-कवच का काम करती है। इसीलिए वर्तमान विकास दर में घरेलू मांग की मजबूती को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।

इस आर्थिक प्रदर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि वृद्धि केवल एक क्षेत्र के सहारे नहीं टिकी है। विनिर्माण क्षेत्र में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि इस बात का संकेत है कि भारत धीरे-धीरे उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लंबे समय तक भारत की अर्थ व्यवस्था को मुख्यतः सेवा क्षेत्र की शक्ति के रूप में देखा जाता रहा,लेकिन अब देश में उत्पादन बढ़ाने,घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने और बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में किए गए प्रयासों से औद्योगिक क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। निर्माण क्षेत्र भी रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सड़कें, रेल,बंदरगाह, हवाई अड्डे, आवास, औद्योगिक गलियारे और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश का प्रभाव केवल आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों में नहीं दिखाई देता,बल्कि उससे भविष्य की आर्थिक क्षमता भी निर्मित होती है।

भारत की वर्तमान आर्थिक यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनाई गई नीतियों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले वर्षों में सरकार ने बुनियादी ढांचे,डिजिटल भुगतान,वित्तीय समावेशन, विनिर्माण, नए उद्यम,आत्मनिर्भरता,ऊर्जा सुरक्षा और औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दिया है। जनधन खातों से लेकर डिजिटल भुगतान तक और राजमार्गों से लेकर रेलवे के आधुनिकी करण तक,आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक तंत्र तैयार हुआ है। वस्तु एवं सेवा कर ने देश के बड़े बाजार को अधिक एकीकृत करने में भूमिका निभाई है। दिवाला एवं दिवालियापन संहिता जैसी व्यवस्थाओं ने कारोबारी वातावरण को अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं ने अनेक क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन और निवेश को बढ़ावा दिया है। इन नीतियों का वास्तविक मूल्यांकन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि उनके परिणामों से होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद के ताजा आंकड़े इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत अवश्य देते हैं।

आम नागरिक के लिए आर्थिक विकास का अर्थ तभी सार्थक है,जब उसके जीवन में रोजगार के अवसर बढ़ें, आय में वृद्धि हो,महंगाई नियंत्रित रहे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों तथा जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार आए। सकल घरेलू उत्पाद हमें अर्थव्यवस्था की गति बताता है,लेकिन यह नहीं बताता कि उस विकास का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक किस प्रकार पहुंच रहा है। इसलिए भारत की अगली चुनौती तेज विकास से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी रोजगार है। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र का विस्तार इसलिए आशाजनक है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन भविष्य में भारत को ऐसे उद्योगों की आवश्यकता होगी, जो बड़ी संख्या में युवाओं को सम्मानजनक और स्थायी रोजगार दे सकें। भारत की युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि उसे कौशल,शिक्षा,तकनीक और रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलते हैं तो यही युवा शक्ति भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की सबसे बड़ी ऊर्जा बन सकती है।

जिनकी नहीं होती मां...

प्रोफेसर शाम लाल कौशल
रोहतक
हरियाणा

जिनकी नहीं होती मां
उसको पूछ कर देखो।
उसके पूरे नहीं होते अरमान
उसको पूछ कर देखो।
रात को देखता रहता है आसमान
इसको पूछ कर देखो।
कोई मुश्किल होती नहीं आसान
उसको पूछ कर देखो।
उसको सूना सूना लगता है जहान
उसको पूछ कर देखो।
किसी भी खुशी का होता नहीं गुमान
उसको पूछ कर देखो।
खाली खाली सा लगता है मकान
उसको पूछ कर देखो।
मां जैसा शख्स है कहां
उससे पूछ कर देखो।
सब कुछ है, लेकिन मां नहीं यहां
उससे पूछ कर देखो।
जब तक मां रहती है जीवित
आदमी रहता है जवान
उससे पूछ कर देखो।
जब स्वर्गवास हो जाती है मां
खाली खाली लगता है
आंगन और मकान
उससे पूछ कर देखो।
अब कोई भी नहीं मुस्कुराता,तोतली हो
गई मेरी ज़ुबान
उस से पूछ कर देखो।

काश ! ये पापी पेट ना रूलाता

उदय किशोर साह
जयपुर,
बांका
बिहार

कैसे भूल जाऊँ अपनी गाँव की पावन मिट्टी।
जेहन में कौंध रहा जिनकी यादें खट्टी मिठी॥
बचपन से सिखाया ना रोना,सदा मस्कुराना ।
शहर में आकर मैं बन गया सबका बेगाना ॥
शुद्ध हवा शुद्ध पानी की नदी थी हमें प्यारी ।
अमुवा के बगीचे में बीतता था वक्त हमारी ॥
पहाड़ों से आती थी जब शेर की दहाड़ ।
सीने में धड़कता था बैरी जन का भी प्यार ॥
बाग बगीचे हरी भरी वन व घर की गुलशन ।
मेहमानों का भी मोह लेते थे उनके चित्तमन ॥
कोयलिया काली काली की करूण पुकार ।
याद आती है नित्य हमें घर व गाँव जवार ॥
माता पिता का था घर में एकलौता दुलारा ।
उनके लिये मैं था एक अनमोल ही सितारा ॥
ये पत्थर के महल ये कंकरीट पथ अनजाना ।
मजबूरी में भी नहीं होता इस शहर में जमाना ॥
काश! ये पापी पेट,जीवन में ना हमें रूलाता ।
रोटी कमाने शहर हमें,कभी ना बुलाता ॥
गाँव की पर्णकुटी था,स्वर्ग सा अपन नजारा ।
सुकून देता था,घर का टुटी खाट पे सारा ॥

संतान प्राप्ति अउ दीर्घायु के कामना बर माता मन रहिथे:हलषष्ठी परब

अशोक पटेल
शिवरीनारायण
छत्तीसगढ़

हलषष्ठी परब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के छठ तिथि के दिन मनाय जाथे। ए कमरछठ, हरछठ के नाम से भी जाने जाथे।

इही दिन भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम के जन्म होय रिसे। ए कारण इही दिन बलराम के जन्मोत्सव के रूप म भी मनाय जाथे । एकर पूजा के साथ-साथ इनकर शस्त्र हल अउ मूसल के भी पूजा करे जाथे। इहाँ ल ध्यान दे के बात ए हावय की हमर देश ह कृषि प्रधान देश आय। जिहाँ किसान अउ उनकर खेती-बाड़ी म कारज म आने वाले उपकरण के विशेष पूजा होथे। इनकर बिना कोनो भी कृषि कार्य ह सम्पन्न नई होवय।अउ इही हर भारतीय संस्कृति के रूप म हमन ल दिखाई देथे। अउ सब के प्रतिनिधि के रूप म बलराम जी ल माने जाथे।ओकरे जईसे पुत्र के कामना करत जम्मो माता मन ए व्रत ल रखथे।माता मन ए दिन संकल्प लेके दीवार म भैंस के गोबर से छट माता के चित्र बनाथे,अउ एकर साथ म गणेश,कार्तिकेय,पार्वती के पूजा करथें। एक छोट अकन तरिया भी बनाय जाथे,जेमा बोईर,परसा अउ काशी के पेड़ ल उगाए जाथे।ओ तरिया म पानी भरे जाथे। अउ ओकर तिर बईठ के माता मन छठ के कथा ल सुनथें।

एकर कथा कुछ ए प्रकार से आथे- चंद्रवत नाम के एक धर्मनिष्ठ राजा रहिस ओहर प्रजा के कल्याणार्थ अड़बड़ अकन तरिया खनवाईस पर ओमा पानी नई रहिस,अवईया-जवईया सब प्रजा मन ह राजा ल भला बुरा कहे लागिन। जब राजा ल ए बात के मालूम होईस त ओला अबड़ दुख होईस। उही रात के राजा ल वरुण देवता के सपना आथे अउ कथे की तय हर अपन इकलौता पुत्र ल बलि देबे त तरिया म पानी हर लबालब भर जाही। ए बात ल राजा हर अपन साभसद मन ल सुनाईस अउ कहिस की चाहे जो भी हो जाए मैं अपन पुत्र के बलि नई दे सकंव। ए बात ल ओकर पुत्र ल पता चल जाथे ओहर धर्म के मर्यादा और प्रजा के हित के लिए अपन आप ल बलि देके स्वयं तरिया म जाके बैईठ जाथे। जईसे ही ओहर तारिया म बैईठिस ओसने ही तरिया ह पानी से लबालब भर जाथे। अपन इकलौता पुत्र के बलि से राजा ल अड़बड़ दुख होथे अउ दुखी हो के ओ हर जंगल डहर चल देथे। उहाँ ओहर देखिस की कुछ एक स्त्री मन कुछ व्रत करत हावय,राजा ओकरा जाके पूछिस,त ओ स्त्री मन पुत्र के मंगल कामना अउ हलषष्ठी के विधान ल बताईस।तब राजा हर विधि-विधान पूर्वक ए व्रत ल करिस।तब ओकर पुत्र ह जीवित हो के तरिया ले बाहिर आगे। ए प्रकार से माता मन पुत्र के दीर्घायु अउ संतान प्राप्ति के लिए ए व्रत करथें। ए दिन माता मन जे जगह नागर चले रहिथे ओ जगह के फसल से बने व्यंजन के उपयोग नई करय। इहाँ-उहाँ तरीया डबरा म अपने अपन जागे पसहर चाउर के उपयोग खीर अउ पांच प्रकार के भाजी बनाके ओकर भोग लगाके अपन व्रत ल पूर्ण करथें।भईंस दूध के सेवन करथें।भईंस के दूध से बने व्यंजन ल ग्रहण करथें।

हमर हिंदू संस्कृति म गाय ल गाउ माता के रूप म मानथें। इही ल कामधेनु कहे जाथे। ठीक अईसन हे महत्व हमर संस्कृति म भईंस के भी हावय।ओकर दूध ह बलवर्धक रहिथे,अउ यम देव के वाहन भी इही भैंसा हर आय।माता मन के द्वारा इही भईंस के दूध से बने चीज के भोग लगाय जाथे। अउ यमराज ले दीर्घायु जीवन के कामना करे जाथे। ए प्रकार से ए व्रत हर लंबा उम्र के प्रतीक माने जाथे।जेमा माता बहिनी मन अपन संतान के लिए और उकार लम्बा उमर के लिए प्रार्थना करथें। ताकि उनकर संतान मन सुख शान्ति आरोग्य अउ दीर्घायु उमर ल प्राप्त कर सकय।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

CMYK

सैनिक स्कूल अंबिकापुर का 18वां स्थापना दिवस समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न

सैनिक स्कूल विद्यार्थियों में अनुशासन,समर्पण और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने निभाती है महत्वपूर्ण भूमिका : मंत्री अग्रवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सैनिक स्कूल अंबिकापुर का 18वां स्थापना दिवस समारोह हर्षोल्लास,उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। समारोह में विद्यालय की 18 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, उपलब्धियों और विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रदर्शित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल रहे। इस अवसर पर सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा,कलेक्टर अजीत वसंत,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल सहित संभाग एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ। अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इसके पश्चात दीप प्रज्ज्वलन के साथ समारोह का विधिवत शुभारंभ हुआ। विद्यालय की 18 वर्षों की यात्रा के उपलक्ष्य में अतिथियों ने केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। विद्यालय के प्राचार्य कर्नल राजेश बैंदा ने सत्र 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने विद्यालय

की शैक्षणिक,खेलकूद एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों तथा विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी दी। समारोह में सैनिक स्कूल के कैडेटों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। स्वागत गीत,छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक-संस्कृति पर आधारित लोकनृत्य,प्रेरणादायक मूक अभिनय, देशभक्ति से ओतप्रोत समूहगान तथा भगवान श्रीराम के जीवन एवं आदर्शों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति ने उपस्थित दर्शकों को प्रभावित किया। मुख्य अतिथि द्वारा सैनिक स्कूल अंबिकापुर की सत्र 2025-26 की विद्यालय पत्रिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर संस्कृत शिक्षक सौरभ कुमार जैन के मार्गदर्शन में कैडेटों द्वारा विकसित अभिनव 'संस्कृत ऐप' का भी अतिथियों ने अवलोकन किया। अतिथियों ने ऐप की उपयोगिता एवं विशेषताओं की सराहना की।

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट एवं हाउस सम्मानित : समारोह में सत्र 2025-26 के दौरान शैक्षणिक,खेलकूद एवं सह-

पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को सम्मानित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हाउस को ट्रॉफियां प्रदान की गईं। सर्वश्रेष्ठ सह-पाठ्यक्रम हाउस का सम्मान कटारी हाउस एवं अरिहंत हाउस को प्रदान किया गया। खेलकूद के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कटारी हाउस एवं अरिहंत हाउस को सम्मानित किया गया। शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन सिंह हाउस एवं तेजस हाउस को सर्वश्रेष्ठ अकादमिक हाउस का सम्मान दिया गया। विद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, स्टाफ एवं जनरल कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य, कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण तथा सैनिक स्कूल अंबिकापुर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कमेंडेशन (प्रशस्तिध्सराहना) प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कैडेटों को अनुशासन,परिश्रम और राष्ट्रसेवा के लिए किया प्रेरित

मुख्य अतिथि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपने संबोधन में सैनिक स्कूल अंबिकापुर की शैक्षणिक,खेलकूद एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में हासिल उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कैडेटों को अनुशासन को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने,निरंतर परिश्रम एवं समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल जैसे संस्थान विद्यार्थियों में अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कैडेटों से इन मूल्यों को आत्मसात करते हुए जीवन में आगे बढ़ने और देश के गौरवशाली एवं जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के उप-प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल डॉ. पी. श्रीनिवास ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों एवं उपस्थित गणमान्यजनों के प्रति आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगान के साथ समारोह का गरिमापूर्ण समापन हुआ।

तंबाकू मांगने पर विवाद, रॉड से युवक के सिर पर किया हमला,इलाज के दौरान मौत

सन्ना में प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर रेफर किया गया था,निजी अस्पताल से रायपुर रेफर होने पर पैसे के अभाव में परिजन घर ले गए

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

तंबाकू मांगने की बात को लेकर हुए विवाद में गांव के ही युवक ने 22 वर्षीय उमेश राम पर रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल उमेश का सन्ना अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर रेफर किया गया। निजी अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे रायपुर रेफर किया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण परिजन उसे घर ले गए। तबीयत बिगड़ने पर दोबारा मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया,जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार उमेश राम पिता जुगे राम ग्राम डोभा का रहने वाला था। वह 28 अगस्त की रात करीब 9 बजे गांव में गया था। इस दौरान उसने गांव के ही रुस्तम से तंबाकू मांगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि तंबाकू मांगने से नाराज रुस्तम ने रॉड से उमेश के सिर पर हमला कर दिया। हमले में उमेश गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे सन्ना अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए अंबिकापुर रेफर कर दिया।

परिजन उसे अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उपचार के बाद डॉक्टरों ने रायपुर रेफर कर दिया। लेकिन इलाज और रायपुर ले जाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होने के कारण परिजन उसे वापस घर ले गए। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने उमेश के इलाज के लिए आरोपी रुस्तम के पिता से आर्थिक मदद मांगी थी। इस पर उन्होंने कथित तौर पर कहा कि यदि थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो इलाज के लिए रुपए नहीं देंगे। बाद में परिजन दोबारा रुपए मांगने पहुंचे, लेकिन मदद नहीं मिली। समुचित इलाज के अभाव में उमेश की तबीयत बिगड़ती गई। इसके बाद उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

गणपति धाम में 20 सितंबर को होगी भव्य महाआरती, मुख्यमंत्री का आगमन प्रस्तावित

गणेश पंडालों और झांकियों को सीनियर-जूनियर वर्ग में दिए जाएंगे पुरस्कार,अनंत चतुर्दशी पर विवेकानंद चौक में होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

गणेश उत्सव 2026 को आस्था, परंपरा और सामाजिक एकता के महापर्व के रूप में मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गणपति स्थापना समिति ट्रस्ट की ओर से इस वर्ष भी गणपति धाम, महामाया पहाड़ में विशेष आयोजन किए जाएंगे। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक यहां विशेष पूजा-अर्चना होगी। अंबिकापुर की वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार गणेश प्रतिमा स्थापना से पहले गणपति धाम से पवित्र मिट्टी लाकर प्रतिमा के नीचे रखी जाती है। इसे'मटकोड़न'की परंपरा के रूप में निभाया जाता है। गणेश चतुर्थी से एक-दो दिन पहले शहर की विभिन्न गणेश उत्सव समितियों के सदस्य गणपति धाम पहुंचकर पवित्र मिट्टी ले जाएंगे। समिति ने श्रद्धालुओं के स्वागत और आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारी शुरू कर दी है।

20 सितंबर को महाआरती : गणपति धाम में 20 सितंबर रविवार को भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इसमें

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शामिल होने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक विभिन्न समाजों के प्रमुखों द्वारा भी गणपति की पूजा-अर्चना की जाएगी।

पंडाल और झांकियों को मिलेगा पुरस्कार : समिति की ओर से शहर के गणेश पंडालों और झांकियों को सीनियर एवं जूनियर वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए स्वतंत्र निर्णायक मंडल गठित किया गया है। पंडालों और झांकियों का मूल्यांकन स्वच्छता, साज-सज्जा, पर्यावरण अनुकूलता और रचनात्मक प्रस्तुति के आधार पर किया जाएगा।

अनंत चतुर्दशी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम : अनंत चतुर्दशी पर विवेकानंद चौक में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा। इसी मंच से चयनित गणेश पंडालों और झांकियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए भी सीनियर एवं जूनियर वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार होंगे। कार्यक्रम में शामिल सभी झांकियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया जाएगा। समिति ने शहरवासियों और गणेश उत्सव समितियों से आयोजन में सहभागी बनने की अपील की है।

नेपाल बाढ़ त्रासदी में दिवंगतों को सरगुजा में श्रद्धांजलि

अम्बिकापुर,01 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ आपदा में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सरगुजा जिले के स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने शोक सभा आयोजित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सरगुजा पुलिस एवं जिले के स्वैच्छिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में संचालित नवा बिहान नशामुक्ति जागरूकता अभियान एवं परामर्श केंद्र से जुड़े कार्यकर्ताओं ने शहर के घड़ी चैक स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लापता लोगों के सकुशल मिलने और मृतकों के परिजनों को संबल मिलने की ईश्वर से प्रार्थना की गई। शोक सभा में नवा बिहान अभियान के संयोजक वरिष्ठ समाजसेवी मंगल पाण्डेय,वरिष्ठ समाजसेविका वंदना दत्ता एवं साहित्यकार संतोष दास 'सरल' ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी अजय तिवारी,सुजान बिंद, सत्यनारायण यादव, बृजबिहारी द्विवेदी, अधिवक्ता सुरेश बुनकर, अंकुर सिन्हा,संजय ठाकुर,विजय किशोर उपाध्याय,संतोष कुमार विश्वकर्मा, हिना खान, रीना ठाकुर, मनीषा सिन्हा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कपड़ा व्यवसायी से मारपीट,7 लोगों पर एफआईआर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

केपी असनीहापारा में लड़ाई के बीच बचाव करना एक युवक को महंगा पड़ गया। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने 7 नामजद सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रेडीमेड कपड़ा बेचने वाले विजय गिरी ने कोतवाली थाना पुलिस को बताया कि 30 अगस्त की शाम करीब 7 बजे वह केपी ऊपरपारा जा रहा था। सूर्या किराना दुकान के पास गौतम और भूरा के बीच लड़ाई हो रही थी। वह समझाने लगा तो नारद और गौतम ने गाली देते हुए तुम बीच-बचाव करने वाले कौन होते हो,कहकर उलझ गए। मना करने पर नारद, गौतम,विष्णु,महेश,ओम कुमार,सुनील, बुदेला और अन्य हाथ-मुक्का,लात से मारपीट करने लगे।

क्रिप्टो में एक साल में 10 हजार से एक लाख करने का झांसा,फरार आरोपी गिरफ्तार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 10 हजार रुपए की ठगी के मामले में मणिपुर पुलिस ने फरार छठे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान त्रिपाल टोप्पो उर्फ गुलाब (53) पिता स्व. रामलाल टोप्पो,निवासी इंदरपुर, थाना दरिमा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोबाइल और नोटबुक जब्त की है। पुलिस के अनुसार इंदरपुर निवासी विद्याचरण राव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव के त्रिपाल टोप्पो ने ऑनलाइन शेयर मार्केट में फायदा होने की बात कहकर उसे योजना से जुड़ने के लिए कहा था। इसके बाद त्रिपाल के माध्यम से उसकी मुलाकात उदयपुर निवासी राजकुमार पैकरा से हुई। राजकुमार ने उसे बिटगेट वॉलेट

एलजीएनएस नामक क्रिप्टो वॉलेट ऐप में निवेश करने पर अधिक रकम मिलने का झांसा दिया। 19 जुलाई को होटल फिल आनंदम में शेयर मार्केट के संबंध में ट्रेनिंग रखी गई थी। यहां कांता प्रसाद राजवाड़े लैपटॉप और प्रोजेक्टर के माध्यम से करीब 10-12 लोगों को ऐप के जरिए पैसा बढ़ाने की जानकारी दे रहा था। इसी दौरान एक साल में 10 हजार रुपए को एक लाख रुपए करने का लालच देकर राजकुमार पैकरा ने प्रार्थी से 10 हजार रुपए लिए। शिकायत पर मणिपुर थाने में धारा 318(4), 61(2) बीएनएस में मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने कांता प्रसाद राजवाड़े,राजकुमार पैकरा,जीवन साय टोप्पो, फिरोज लकड़ा और मुकेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था।

मोबाइल और नोटबुक जब्त : फरार आरोपियों की तलाश के दौरान पुलिस ने त्रिपाल टोप्पो को पकड़ा। पूछताछ में उसके द्वारा भी बिटगेट वॉलेट एलजीएनएस के प्रचार-प्रसार से जुड़े होने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल और एक नोटबुक को जब्त किया है। पुलिस के अनुसार इस योजना का छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के साथ देश के दूसरे राज्यों में भी प्रचार-प्रसार किए जाने की जानकारी मिली है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

नौ साल पुराने मारपीट के मामले में स्थायी वारंटी गिरफ्तार कोतवाली पुलिस ने गुदरी बाजार से आरोपी को पकड़ा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

नौ वर्ष पुराने मारपीट के मामले में फरार चल रहे स्थायी वारंटी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी की पहचान विकास यादव (24) पिता सीताराम यादव, निवासी गुदरी बाजार, अंबिकापुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ धारा 294, 506, 323 और 324 भादवि के तहत मामला दर्ज था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद न्यायालय ने उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया था। एसएसपी के निर्देश पर लंबे समय से लंबित स्थायी वारंटों की तामीली के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण यादव, आरक्षक अभिषेक सिंह और संजीव पांडेय शामिल रहे।

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में प्रसव सेवा शुरू....

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन में अम्बिकापुर के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर प्रसव सेवा शुरू की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी एस मार्को के निर्देशन में 01 सितंबर 2026 को रात्रि 01: 30 बजे पहला सफलतापूर्वक प्रसव कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रसव से स्वस्थ नवजात शिशु का जन्म हुआ, जिसका वजन 2.570 किलोग्राम है। प्रसव उपरांत चिकित्सकीय परीक्षण में माता एवं नवजात दोनों स्वस्थ पाए गए। जच्चा एवं बच्चा दोनों की आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल एवं निगरानी की जा रही है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में सुरक्षित प्रसव सेवा की शुरुआत क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को स्थानीय स्तर पर सुलभ,सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसव सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए दूरस्थ स्वास्थ्य संस्थानों पर निर्भरता कम होगी तथा आवश्यकता के अनुसार समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। सफल प्रसव में केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ.अपूर्व जायसवाल तथा स्टाफ नर्स क्रांति, प्रियंका एवं हिमांशी, संस्था के समस्त कर्मचारियों,एमटी तथा मितानिन अलका का योगदान रहा।

CMYK

7.18 करोड़ की सड़क में धंसा रास्ता,ह्यूम पाइप के आसपास मिट्टी गायब-कौन देगा जवाब?

पहले देरी,फिर गुणवत्ता पर सवाल और अब सड़क धंसी! गंगोटी-शिवपुर मार्ग पर पीडब्ल्यूडी कटघरे में...

एस्टीमेट में मजबूत सड़क,जमीन पर धंसता रास्ता! 7.18 करोड़ की परियोजना पर बड़ा सवाल...

ठेकेदार को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, सड़क फिर भी अधूरी...अब बारिश ने दिखा दी असली तस्वीर!

कागजों में करोड़ों की सड़क,जमीन पर गड्ढे और धंसाव! पीडब्ल्यूडी की निगरानी पर सवाल...

ह्यूम पाइप डाला,मिट्टी भरी और छोड़ दिया? बारिश आते ही धंस गई 7.18 करोड़ की सड़क!

5 महीने का काम,14 महीने में भी अधूरा...जो बना वो भी बैठ गया...आखिर जिम्मेदार कौन?

गंगोटी-शिवपुर सड़कः विकास की राह या कमीशन का गलियारा? पहली बारिश में धंसाव ने बढ़ाए सवाल...

दैनिक घटती-घटना का अंदेशा सच होता दिखा...गुणवत्ता पर उठे सवालों के बीच सड़क में बड़ा धंसाव...

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,01 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

गंगोटी से शिवपुर नवापारा तक बनने वाली 5.10 किलोमीटर सड़क को लेकर दैनिक घटती घटना ने निर्माण की शुरुआत से ही जो सवाल उठाए थे,अब मौके की तस्वीरें उन सवालों को और गंभीर बना रही हैं, समय पर सड़क नहीं बनी,गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठे और अब बारिश के बाद सड़क के नीचे की संरचना के बैठने की तस्वीर सामने आ गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कार्यादेश के अनुसार इस सड़क की अनुमानित लागत 718.42 लाख यानी करीब 7.18 करोड़ रुपये है,कार्यादेश 30 जून 2025 को जारी हुआ था और इसमें कार्य की अवधि 5 माह 00 दिन,वर्षा ऋतु सहित निर्धारित की गई थी,ठेका मे.जवाहरलाल गुप्ता को दिया गया था और स्वीकृत दर SOR से 18.18 प्रतिशत कम थी,यानी जिस सड़क को नवंबर

2025 के आसपास पूरा हो जाना चाहिए था,वह सितंबर 2026 में भी पूरी नहीं हुई है,अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सड़क कब बनेगी,बल्कि सवाल यह भी है कि जो हिस्सा बनाया गया, वह पहली ही बरसात में क्यों बैठने लगा?

जिस बात का अंदेशा था, वही तस्वीर सामने आ गई- निर्माण के दौरान पहले भी यह सवाल उठाया गया था कि सड़क का काम एस्टीमेट और तकनीकी मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं,उस समय यह आशंका जताई गई थी कि यदि सड़क के नीचे पानी की निकासी के लिए लगाए जा रहे पाइपों और उनके आसपास की संरचना को उचित तरीके से तैयार नहीं किया गया तो बरसात में सड़क बैठ सकती है,अब सामने आई तस्वीरों में सड़क की सतह के नीचे गहरी मिट्टी धंसने और खाली जगह बनने जैसी स्थिति दिखाई दे रही है,एक स्थान पर सड़क के नीचे लगा पाइप स्पष्ट दिखाई दे रहा है और उसके आसपास की मिट्टी बड़े हिस्से में हटती या धंसी हुई नजर आती है,सड़क के ऊपर का हिस्सा भी प्रभावित दिखाई दे रहा है,यह तस्वीरें अपने आप में निर्माण दोष का अंतिम तकनीकी प्रमाण नहीं हैं, लेकिन इतनी गंभीर स्थिति निश्चित रूप से तत्काल तकनीकी जांच की मांग करती है।

ह्यूम पाइप के ऊपर सड़क, नीचे धंसी मिट्टी—कहां हुई चूक?- सड़क में पानी की निकासी के लिए 600 मिमी व्यास के RCC NP-x/Prestressed Concrete Pipe का प्रावधान BOQ में दर्ज है, अंतिम BOQ में इसकी मात्रा 110 मीटर दी गई है,लेकिन मौके की तस्वीर में जिस स्थान पर पाइप दिखाई दे रहा है,वहां उसके आसपास और ऊपर की मिट्टी में गंभीर धंसाव नजर आ रहा है, यहीं से सबसे बड़ा तकनीकी सवाल पैदा होता है क्या पाइप की बेडिंग,जॉइंटिंग,बैकफिलिंग और कम्पेक्शन निर्धारित तकनीकी प्रक्रिया के अनुसार किया गया था? क्या पाइप के दोनों ओर और ऊपर पर्याप्त रूप से स्वीकृत सामग्री डाली गई? क्या उस सामग्री को निर्धारित तरीके से परत-दर-परत कम्पैक्ट किया गया? क्या पानी के दबाव और मिट्टी के कटाव को ध्यान में रखकर सुरक्षा व्यवस्था की गई? इन सवालों का जवाब केवल मौके पर निरीक्षण और तकनीकी परीक्षण से ही मिल सकता है।

सिर्फ पाइप डाल देना ही सड़क निर्माण नहीं- सड़क के नीचे पाइप डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल देना पर्याप्त नहीं होता, कलवर्ट अथवा पाइप क्रॉसिंग की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उसके आसपास की संरचना किस तरह तैयार की गई, पाइप को किस आधार पर रखा गया और बैकफिलिंग व कम्पेक्शन किस गुणवत्ता से हुआ,वर्क ऑर्डर में सड़क निर्माण के अलावा संरचनात्मक एवं कलवर्ट संबंधी कई मदें शामिल हैं,दस्तावेज में पाइप कलवर्ट के लिए प्रथम श्रेणी की बेडिंग तथा अन्य संबंधित कार्यों का उल्लेख है,ऐसे में अब विभाग को यह बताना चाहिए कि मौके पर लगाए गए पाइप की बेडिंग और उसके आसपास की बैकफिलिंग किस मानक से की गई थी।

पहली बारिश में सड़क का बैठना सामान्य है या निर्माण की खामी?- यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, निर्माणाधीन सड़क पर बारिश के बाद कुछ अस्थायी क्षति होना संभव हो सकता है,लेकिन यदि सड़क के नीचे बड़ा खोखलापन बन जाए,मिट्टी धंस जाए और ऊपर की सड़क की संरचना प्रभावित हो जाए, तो इसे सामान्य मानकर छोड़ना उचित नहीं होगा, इसलिए विभाग को मौके पर तत्काल जांच कर यह निर्धारित करना चाहिए कि धंसाव का कारण क्या है–जलभराव? अपर्याप्त कम्पेक्शन? पाइप के आसपास खराब बैकफिलिंग? मिट्टी का कटाव? ड्रेनेज डिजाइन की समस्या? या निर्माण प्रक्रिया में कोई तकनीकी कमी? बिना जांच के किसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। लेकिन जांच न करना उससे भी बड़ा सवाल होगा।

सड़क की हालत देखकर आवागमन भी खतरे में- ताजा तस्वीरों में सड़क के कई हिस्से बारिश के पानी से भरे दिखाई दे रहे हैं, कहीं गहरी कीचड़ है तो कहीं गिट्टी और मिट्टी का मिश्रण सड़क की सतह पर फैला है,ऐसे मार्ग से दोपहिया वाहनों और ग्रामीणों का आवागमन मुश्किल हो रहा है,जिस सड़क से ग्रामीणों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलनी थी,वही निर्माण अवधि में परेशानी का कारण बनती जा रही है, सबसे चिंता की बात यह है कि सड़क अभी पूरी भी नहीं हुई है और निर्माणाधीन हिस्से में ही इस प्रकार की समस्याएं सामने आने लगी हैं।

5 महीने की समय-सीमा कहां गई?- कार्यादेश में स्पष्ट रूप से 5 माह 00 दिन की कार्य अवधि दी गई थी,अब निर्धारित अवधि समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है,इसलिए अब विभाग से केवल सड़क पूरी करने की तारीख पूछना पर्याप्त नहीं है। जनता को यह भी बताया जाना चाहिए कि अब तक कितनी बार एक्सटेंशन दिया गया? पहला एक्सटेंशन कब दिया गया? दूसरा एक्सटेंशन कब दिया गया? कुल कितने दिनों की समय-वृद्धि स्वीकृत हुई? अगली पूर्णता तिथि क्या निर्धारित की गई है? क्या विलंब के लिए ठेकेदार को नोटिस दिया गया? कितने नोटिस जारी हुए? क्या किसी प्रकार का दंड लगाया गया? क्या समय-वृद्धि के लिए सक्षम अधिकारी से विधिवत अनुमति ली गई? इन सवालों का जवाब विभागीय फाइलों में जरूर होना चाहिए।

एक्सटेंशन की फाइल जनता के सामने क्यों नहीं?- यदि ठेकेदार को समय पर काम पूरा करने में कठिनाई हुई और विभाग ने नियमों के तहत समय-वृद्धि दी, तो उसके कारण भी स्पष्ट होने चाहिए,यदि बारिश,भूमि अधिग्रहण, साइट की समस्या,तकनीकी परिवर्तन या अन्य कोई वास्तविक कारण था तो उसका दस्तावेजी रिकॉर्ड होना चाहिए,लेकिन यदि बार-बार समय-वृद्धि दी गई और काम की गति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ,तो फिर अनुबंध प्रबंधन और विभागीय निगरानी दोनों की समीक्षा जरूरी है,सवाल यह नहीं कि एक्सटेंशन दिया जा सकता है या नहीं, सवाल यह है कि एक पांच महीने की परियोजना लगातार कितने समय तक एक्सटेंशन पर चल सकती है और प्रत्येक एक्सटेंशन के पीछे वास्तविक कारण क्या है?

18.18% कम दर पर ठेका—अब हर लेयर की जांच जरूरी- इस सड़क का काम स्कूक से 18.18 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत हुआ था, कम दर पर काम मिलना अपने आप में कोई गड़बड़ी नहीं है,लेकिन जब निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठें,सड़क की गति धीमी हो और निर्माणाधीन हिस्से में धंसाव जैसी स्थिति सामने आए,तो विभाग को गुणवत्ता परीक्षणों को सार्वजनिक करने की जरूरत बढ़ जाती है, सड़क की बेस,सब-बेस,कम्पेक्शन और बिटुमिनस कार्य की तकनीकी जांच होनी चाहिए, वर्क ऑर्डर में प्राइम कोट,टैक कोट और बिटुमिनस मैकडम जैसे कार्य भी शामिल हैं,ऐसे में यह भी देखा जाना चाहिए कि जहां-जहां कार्य पूरा बताया जा रहा है,वहां वास्तविक मोटाई और गुणवत्ता स्वीकृत एस्टीमेट के अनुरूप है या नहीं।

60 महीने की गारंटी है,लेकिन क्या जनता को 60 महीने इंतजार करना होगा?- कार्यादेश में कार्य पूर्ण होने के बाद 60 माह की परफॉर्मेंस गारंटी का प्रावधान है,लेकिन गारंटी का मतलब यह नहीं कि निर्माण के समय गुणवत्ता से समझौता किया जा सकता है और खराब होने के बाद ठेकेदार उसे सुधार देगा,जनता को मजबूत सड़क चाहिए, ऐसी सड़क नहीं जिसे हर बारिश के बाद मरम्मत की जरूरत पड़े,यदि सड़क निर्माण के दौरान ही कहीं धंसाव हो गया है तो विभाग को इसे 'वारंटी में ठीक हो जाएगा' कहकर टालने के बजाय यह पता लगाना होगा कि धंसाव हुआ क्यों।

क्या विभागीय इंजीनियरों ने मौके की जांच की?- अब सबसे बड़ा सवाल विभागीय इंजीनियरिंग व्यवस्था पर है,जिस सड़क पर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं,उसकी निगरानी के लिए विभागीय अधिकारी और इंजीनियर मौजूद हैं,यदि पाइप के आसपास बैकफिलिंग या कम्पेक्शन में कमी हुई है,तो उसे सड़क की अगली लेयर डालने से पहले ही पकड़ लिया जाना चाहिए था,यदि कमी नहीं थी और बाद में असामान्य धंसाव हुआ,तब भी तकनीकी टीम को यह पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, मौके का निरीक्षण,लेवल की जांच,धंसे हिस्से की खुदाई,पाइप की स्थिति,बेडिंग, बैकफिल सामग्री और कम्पेक्शन की जांच–इन सभी की आवश्यकता हो सकती है।

कमीशन के आरोपों पर भी हो निष्पक्ष जांच- क्षेत्र में अब यह चर्चा भी तेज है कि क्या ठेकेदार और विभाग के बीच किसी प्रकार की मिलीभगत के कारण कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ लोग इसे 'कमीशन का गलियारा' तक कह रहे हैं, हालांकि किसी अधिकारी या ठेकेदार पर कमीशन लेने का आरोप बिना प्रमाण के तथ्य के रूप में नहीं लगाया जा सकता,लेकिन यदि काम समय पर पूरा नहीं हुआ,गुणवत्ता पर लगातार शिकायतें हुईं,निर्माण में तकनीकी खामियां सामने आईं,फिर भी लगातार समय-वृद्धि मिलती रही, नोटिस और कार्रवाई का असर दिखाई नहीं दिया, तो इन सभी परिस्थितियों की स्वतंत्र जांच जरूर होनी चाहिए।

विकास कॉरिडोर या कमीशन का गलियारा?- जिस परियोजना को ग्रामीणों के लिए विकास का रास्ता बनना था,उसकी मौजूदा तस्वीर देखकर सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर यह सड़क विकास का कॉरिडोर बन रही है या ठेकेदार और विभागीय व्यवस्था की लापरवाही का रास्ता? तस्वीरें किसी कमीशन का प्रमाण नहीं हैं, लेकिन वे यह जरूर दिखाती हैं कि सड़क के कुछ हिस्सों में गंभीर भौतिक समस्या मौजूद है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए 'कमीशन का गलियारा' अभी जांच का सवाल है,निष्कर्ष नहीं।

अब विभाग को फाइल खोलकर जवाब देना होगा- गंगोटी-शिवपुर नवापारा सड़क के मामले में अब जनता को केवल आश्वासन नहीं चाहिए,विभाग को सामने आकर बताना चाहिए, कार्यादेश 30 जून 2025, निर्धारित अवधि 5 माह,सड़क की लंबाई, 5.10 किमी,अनुमानित लागतः 718.42 लाख, ठेकेदार मे. जवाहरलाल गुप्ता, स्वीकृत दर, SOR से 18.18% कम,परफॉर्मेंस गारंटी, 60 माह और अब इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने आनी चाहिए पहली निर्धारित पूर्णता तिथि क्या थी? कितनी बार एक्सटेंशन मिला? अगली पूर्णता तिथि क्या है? कितने नोटिस जारी हुए?

विलंब पर कितना दंड लगाया गया? कितने प्रतिशत काम का भुगतान हो चुका है? अब तक कितने गुणवत्ता परीक्षण हुए? और सबसे अहम–बारिश के बाद धंसी सड़क और पाइप के आसपास की मिट्टी की तकनीकी जांच कब होगी? क्योंकि अब मामला सिर्फ 'सड़क कब पूरी होगी' का नहीं रह गया है. अब सवाल है की जो सड़क बनी ही नहीं, वह बैठ कैसे गई? और अगर निर्माण के दौरान ही सड़क के नीचे धंसाव शुरू हो गया है, तो विभाग को यह साबित करना होगा कि 7.18 करोड़ रुपये की यह परियोजना वास्तव में मजबूत सड़क के लिए है या सिर्फ कागजों पर पूरा होने वाली एक और सरकारी कहानी बनकर रह जाएगी।

ड्रंक एंड ड्राइव के मामले मे मोटरसायकल चालक कों 10000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,01 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा मे डीआ.ईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सखती से कार्यवाही की जा रही हैं,इसी क्रम मे यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग मोटरसायकल क्रमांक सीजी /29/ए जे/8364 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम सत्यम आत्मज चन्द्रिका प्रसाद साकिन गोरगी थाना चंदौरा जिला. सूरजपुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, मोटरसायकल चालक द्वारा शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे वाहन चालक को 10000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

जिला अस्पताल जशपुर में गंभीर मरीजों का सफल उपचार...सेप्टिक शॉक में 10 वर्षीय बच्ची की जान बचाई,एक्टोपिक प्रेग्नेंसी का सफल ऑपरेशन

-संवाददाता-

जशपुरनगर,01 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जिला चिकित्सालय जशपुर में गंभीर एवं आपातकालीन मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं और आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। चिकित्सकों एवं नर्सिंग टीम की तत्परता, त्वरित चिकित्सकीय निर्णय और बेहतर समन्वय से हाल ही में दो गंभीर मरीजों का सफल उपचार किया गया। एक ओर सेप्टिक शॉक की गंभीर स्थिति में जिला चिकित्सालय पहुंची 10 वर्षीय बच्ची को समय पर उपचार और सतत निगरानी से स्वास्थ्य लाभ मिला, वहीं दूसरी ओर एक्टोपिक प्रेग्नेंसी के गंभीर मामले में महिला की सफल सर्जरी कर उसे संभावित गंभीर जटिलताओं से बचाया गया। जिला अस्पताल में

उपलब्ध इन सेवाओं से मरीजों को उपचार के लिए दूसरे राज्यों अथवा बड़े चिकित्सा संस्थानों में जाने में लगने वाले अतिरिक्त समय और खर्च से राहत मिल रही है। पाकड़टोली, जिला गुमला निवासी 10 वर्षीय संध्या कुमारी को 28 अगस्त 2026 को तेज बुखार, अत्यधिक कमजोरी, सुस्ती एवं बेहोशी जैसी गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय जशपुर लाया गया। अस्पताल पहुंचने के समय बच्ची का ब्लड प्रेशर एवं ब्लड शुगर काफी कम था। जांच में किडनी एवं लिवर फंक्शन में भी गंभीर असामान्यताएं पाई गईं। चिकित्सकीय परीक्षण के बाद बच्ची की स्थिति को सेप्टिक शॉक की गंभीर अवस्था के रूप में चिन्हित किया गया। बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पुष्पराज प्रधान के नेतृत्व में तत्काल उपचार शुरू किया गया। उसे IV Fluids, उच्च श्रेणी की एंटीबायोटिक्स एवं आवश्यक सपोर्टिव उपचार दिया गया। लगातार कम रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए लगभग तीन दिनों तक Vasoactive/Life-saving Support की आवश्यकता पड़ी। उपचार के दौरान चिकित्सकीय एवं नर्सिंग टीम ने बच्ची के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, चेतना की स्थिति तथा अन्य आवश्यक पैरामीटर की लगातार निगरानी की।

लॉकर से सोने का जेवरात गायब,काम वाली बाई पर संदेह

-संवाददाता-

लखनपुर,01 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

नगर के एक हार्डवेयर व्यापारी के घर लॉकर से करीब एक लाख रुपये का सोने का जेवर चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी लखनपुर थाने में दी गई है,जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, मुख्य मार्ग में रहने वाले अंकुश अग्रवाल ने पुलिस को बताया है कि वर्ष 2018 में विवाह के समय उसके माता-पिता ने पत्नी निकिता अग्रवाल को मुंह दिखाई में सोने का पेंडल सेट एक नग, सोने की कान की बाली दो नग और सोने की अंगूठी दो नग दी थी। जेवरों को उनकी पत्नी त्योहार या रिश्तेदारी में कार्यक्रम होने पर पहनती थी और बाद में लॉकर में रख देती थी। 27 अगस्त को सुबह करीब 9 बजे रक्षाबंधन के मौके पर निकिता जेवरातों को पहनने के लिए लॉकर तक गई तो उसमें चाबी लगा था और अंदर रखा जेवरातों का डब्बा गायब था। इसकी जानकारी वह अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों को दी। घर में काफी खोजबीन के बाद भी जेवर नहीं मिले। व्यवसायी ने बताया है कि उनके घर में काम करने वाली बाई इस घटना के दूसरे दिन से काम पर नहीं आ रही है, ऐसे में उन्होंने उक्त महिला पर ही जेवरातों की चोरी करने का संदेह व्यक्त किया है।

CMYK

साधना निलंबित होकर कलेक्टर की बैठक में कैसे, रिजवान की FIR का कागज ओड़गी में क्यों अटका?

धान की बोरी कम हुई तो रिजवान पर एफआईआर चली...कागज ओड़गी पहुंचा...फिर रास्ते में गायब!

साधना निलंबित हैं...फिर भी कलेक्टर की बैठक में हाजिर...सहकारिता विभाग में नियमों का अपना 'रूट'!

सावारावां में धान की कमी पर कार्रवाई के लिए एफआईआर का पत्र शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ओड़गी को भेजे जाने का दावा...

सूत्रों का आरोप...कागज दबा दिया गया, शिवप्रसादनगर की साधना की कथित बैठक में मौजूदगी ने बढ़ाए सवाल...

बर्खास्तगी के बाद बहाली,फिर निलंबन की स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं,एक तरफ धान की कमी की भरपाई का मौका

दूसरी तरफ एफआईआर की प्रक्रिया पर सवाल...सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे गंभीर प्रश्न

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,01 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सहकारिता विभाग में धान खरीदी से जुड़े मामलों में कार्रवाई और जवाबदेही का सवाल लगातार गहराता जा रहा है,सावारावां समिति में धान की कमी सामने आने के बाद धान खरीदी प्रभारी रिजवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी सामने आई है,बताया जा रहा है कि एफआईआर के लिए तैयार किया गया पत्र/दस्तावेज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित,ओड़गी के शाखा प्रबंधक को दिया गया था लेकिन सूत्रों का दावा है कि यह कागज आगे पुलिस कार्रवाई के लिए बढ़ने के बजाय शाखा स्तर पर ही दबा दिया गया और एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी,इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी आवश्यक है। इधर शिवप्रसादनगर समिति की धान खरीदी प्रभारी साधना कुशवाहा का मामला भी अब इसी सवाल से जुड़ गया है,साधना को निलंबित किए जाने की जानकारी है,उनके संबंध में बर्खास्तगी के बाद बहाली और फिर निलंबन की कार्रवाई को लेकर भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है,इसके बावजूद प्राप्त जानकारी के अनुसार वह जिला मुख्यालय में कलेक्टर द्वारा बुलाई गई बैठकों में बार-बार उपस्थित हो रही हैं,अब सवाल सीधा है यदि साधना कुशवाहा अभी भी निलंबित हैं तो कलेक्टर की बैठक में उनकी उपस्थिति किस हैसियत से हो रही है? और यदि उनका निलंबन समाप्त कर दिया गया है तो उसका आदेश सार्वजनिक क्यों नहीं है? दूसरी तरफ सावारावां में सवाल है की यदि रिजवान के विरुद्ध एफआईआर कराने का निर्णय हो चुका था और पत्र शाखा प्रबंधक तक पहुंच चुका था तो अपराध दर्ज क्यों नहीं हुआ? यानी एक तरफ एफआईआर का कागज, दूसरी तरफ निलंबन का आदेश दोनों ही अब जवाब मांग रहे हैं।

सावारावां में धान की कमी से शुरू हुआ मामला

सावारावां धान खरीदी समिति में खरीदी के दौरान धान की कमी पाए जाने की बात सामने आई थी,मामले को लेकर विभागीय स्तर पर जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई,जानकारी के अनुसार धान खरीदी प्रभारी रिजवान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार किए गए,यह भी बताया जा रहा है कि एफआईआर के लिए संबंधित पत्र जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित ओड़गी के शाखा प्रबंधक को दिया गया था,यहीं से मामला एक नए सवाल में बदल गया,यदि शाखा प्रबंधक के पास एफआईआर कराने से संबंधित दस्तावेज पहुंचा था तो उसके बाद क्या हुआ? क्या उसे थाने भेजा गया? क्या पुलिस को दस्तावेज प्राप्त हुए? यदि प्राप्त हुए तो एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? और यदि शाखा प्रबंधक स्तर पर ही मामला रुका तो किस कारण से? इन सवालों का जवाब संबंधित दस्तावेजों और पत्राचार से ही मिल सकता है।

सूत्रों का दावा...एफआईआर का कागज दबा दिया गया

इस मामले में सूत्रों का दावा सबसे गंभीर है, सूत्रों के अनुसार रिजवान के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए भेजा गया कागज शाखा प्रबंधक के स्तर पर दबा दिया गया,जिसके कारण मामला पुलिस तक आगे नहीं बढ़ सका,यह फिलहाल सूत्रों का दावा है और इसकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि जरूरी है,लेकिन यदि यह दावा सही साबित होता है तो सवाल केवल रिजवान तक सीमित नहीं रहेगा,तब यह जांच का विषय होगा कि एफआईआर की कार्रवाई रोकने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया और उसके पीछे क्या कारण था,किसी मामले में अपराध दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू करने के बाद उसे रोकना सामान्य प्रशासनिक निर्णय नहीं माना जा सकता,यदि विभाग को लगता था कि एफआईआर आवश्यक नहीं है तो उसका कारण रिकॉर्ड में होना चाहिए,और यदि एफआईआर जरूरी थी तो फिर उसे आगे बढ़ाने में देरी क्यों हुई?

धान की कमी पूरी करने का अवसर भी चर्चा में-सावारावां मामले में यह भी जानकारी सामने आई है कि धान की कमी पाए जाने के बाद संबंधित पक्ष को कमी पूरी करने का अवसर दिया गया,यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ एफआईआर की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही थी, दूसरी तरफ कमी पूरी करने का अवसर दिया गया,अब यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि यह अवसर किस अधिकारी के आदेश पर,किस नियम के तहत और किस प्रक्रिया के अनुसार दिया गया,क्या कमी की भरपाई होने के बाद भी एफआईआर की प्रक्रिया जारी रहनी थी? क्या विभागीय और आपराधिक कार्रवाई अलग-अलग थी? क्या कमी पूरी होने के बाद स्टॉक का दोबारा सत्यापन हुआ? क्या उसकी रिपोर्ट तैयार हुई? और यदि कमी पूरी हो गई तो क्या इससे पहले की कथित अनियमितता स्वतः समाप्त हो जाती है? इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग को देना होगा।

निलंबित प्रबंधक और फिर भी कमी शून्य करने की कवायद-सावारावां समिति के प्रबंधक के निलंबित होने की जानकारी भी सामने आई है,इसके बावजूद धान की कमी को शून्य करने की कवायद चलने की बात कही जा रही है,यदि कर्मचारी निलंबित है तो यह जानना जरूरी है कि कमी पूरी करने की प्रक्रिया की निगरानी कौन कर रहा है,क्या किसी अन्य अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई? क्या समिति के स्टॉक का दोबारा भौतिक सत्यापन हुआ? क्या रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक का मिलान किया गया? क्या कमी पूरी होने के बाद विभाग ने लिखित रूप से उसे स्वीकार किया? इन सभी सवालों के जवाब बिना दस्तावेज के नहीं मिल सकते।

अब शिवप्रसादनगर की साधना कुशवाहा का मामला-दूसरी ओर शिवप्रसादनगर समिति की धान खरीदी प्रभारी साधना कुशवाहा का मामला भी लंबे समय से सवालों में है,उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है,साथ ही उनके संबंध में बर्खास्तगी के बाद बहाली को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं,यदि बर्खास्तगी हुई थी तो बहाली किस आदेश से हुई? किस अधिकारी ने बहाली की? किन परिस्थितियों में बहाली की गई? क्या विभागीय जांच में कोई निर्णय आया? क्या आरोप समाप्त किए गए? या बहाली के बाद फिर निलंबन की कार्रवाई की गई? इन सवालों का स्पष्ट जवाब अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है।

निलंबन के बाद कलेक्टर की बैठक में मौजूदगी ने बढ़ाया विवाद-मामले का सबसे नया और गंभीर पहलू साधना कुशवाहा की कलेक्टर द्वारा बुलाई गई बैठकों में कथित उपस्थिति है,प्राप्त जानकारी के अनुसार वह जिला मुख्यालय में आयोजित बैठकों में बार-बार उपस्थित हो रही हैं,यदि उनका निलंबन प्रभावी है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उन्हें बैठक में किस हैसियत से बुलाया गया। क्या कलेक्टर कार्यालय ने उन्हें आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया? क्या सहकारिता विभाग ने उन्हें बैठक में भेजा? क्या बैठक में उनकी उपस्थिति केवल जानकारी देने के लिए थी? क्या निलंबित कर्मचारी को ऐसी बैठक में उपस्थित रहने की अनुमति देने वाला कोई आदेश है? या फिर उनके निलंबन की स्थिति बदल चुकी है?

निलंबन जारी है तो आदेश दिखाइए, बहाली हुई है तो वह भी बताइए-इस पूरे मामले का समाधान बेहद सरल है, यदि साधना कुशवाहा अभी भी निलंबित हैं तो उनका वर्तमान निलंबन आदेश सामने रखा जाए और यह बताया जाए कि उन्हें कलेक्टर की बैठक में किस अधिकार से शामिल किया गया,यदि उनका निलंबन समाप्त हो चुका है तो निलंबन समाप्ति या बहाली का आदेश सार्वजनिक किया जाए,यदि वह केवल बैठक में जानकारी देने के लिए अधिकृत थीं तो उस अनुमति का पत्र सामने रखा जाए,इससे पूरा विवाद खत्म हो सकता है, लेकिन जब रिकॉर्ड सामने नहीं आता तो सवाल बढ़ते जाते हैं।

क्या निलंबन सिर्फ कागज पर रह गया?-यहीं से सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर व्यंग्यात्मक सवाल खड़ा होता है,''**कागज कहता है...निलंबित,बैठक कहती है...हाजिर**'',तो फिर जनता किसे सही माने? अगर कर्मचारी कार्य से पृथक है तो बैठक में क्यों? और अगर बैठक में आना जरूरी है तो निलंबन की वास्तविक सीमा क्या है? क्या निलंबन का अर्थ सिर्फ इतना है कि कर्मचारी अपने पुराने पद पर नहीं बैठेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर जिला मुख्यालय की बैठकों में उपस्थित हो सकता है? यदि ऐसा नियम है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

बर्खास्तगी से बहाली तक की फाइल भी सार्वजनिक हो-साधना कुशवाहा के मामले में बर्खास्तगी और बहाली की स्थिति स्पष्ट करना भी जरूरी है,यदि किसी कर्मचारी को बर्खास्त किया गया और बाद में बहाल किया गया तो यह सामान्य प्रशासनिक घटना नहीं है,उसके पीछे आदेश,कारण और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति होनी चाहिए,फिर यदि उसी कर्मचारी को निलंबित किया गया तो निलंबन का आधार भी स्पष्ट होना चाहिए,यानी पूरा घटनाक्रम एक समयरेखा में सामने आना चाहिए बर्खास्तगी ? बहाली ? निलंबन ? वर्तमान स्थिति ? कलेक्टर बैठक में उपस्थिति, तभी यह पता चलेगा कि वास्तव में प्रशासनिक स्तर पर क्या हुआ।

शिवप्रसादनगर समिति में दोबारा प्रभार पर भी सवाल- पूरे प्रकरण में एक और आरोप यह भी है कि पूर्व में अनियमितता अथवा वित्तीय गड़बड़ी के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को शिवप्रसादनगर समिति का प्रभार दोबारा सौंपा गया,यदि यह तथ्य रिकॉर्ड से प्रमाणित होता है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, किस अधिकारी ने प्रभार सौंपा? क्या सक्षम अनुमति ली गई? क्या पूर्व कार्रवाई का रिकॉर्ड देखा गया? क्या कोई विभागीय रोक थी? यदि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई लंबित थी तो फिर उसे दोबारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का औचित्य क्या था?

'संरक्षण तंत्र' की चर्चा क्यों?- सावारावां में एफआईआर के लिए कागज जाने के बाद अपराध दर्ज न होना और शिव प्रसादनगर में निलंबन के बावजूद साधना की कथित बैठक में मौजूदगी–इन दोनों घटनाओं को लेकर क्षेत्र में अब तरह-तरह की चर्चाएं हैं, इसी बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सहकारिता विभाग में पहुंच और संरक्षण का कोई तंत्र काम कर रहा है? यह आरोप है, प्रमाणित तथ्य नहीं, लेकिन यदि विभाग इस तरह की चर्चाओं को गलत मानता है तो उसे दस्तावेज सामने रखकर स्थिति स्पष्ट करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

क्या 'गलती करो और बाद में मामला सेटल करो' जैसी व्यवस्था है?-धान खरीदी समिति में अनियमितता का मामला किसानों और सरकारी संपत्ति से जुड़ा होता है,इसलिए यदि धान की कमी सामने आती है तो जिम्मेदारी तय करना जरूरी है,लेकिन यदि पहले एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हो,फिर कमी पूरी करने का मौका मिले और बाद में एफआईआर ही दर्ज न हो,तो सवाल उठना स्वाभाविक है, इसी तरह यदि निलंबित कर्मचारी को महत्वपूर्ण बैठकों में उपस्थित होने की अनुमति मिलती है तो उस अनुमति का आधार भी स्पष्ट होना चाहिए,वरना जनता के बीच यह धारणा बनती है कि क्या यहां नियम से ज्यादा पहुंच काम करती है? इस धारणा को खत्म करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है।

जांच में किन दस्तावेजों की जरूरत?

मामले को पूरी तरह साफ करने के लिए निम्न रिकॉर्ड सामने लाए जाने चाहिए...

सावारावां समिति

- धान की कमी की जांच रिपोर्ट।
- रिजवान के विरुद्ध एफआईआर की अनुशंसा/पत्र।
- शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ओड़गी को भेजा गया पत्र।
- पत्र की प्राप्ति का रिकॉर्ड।
- थाने को भेजे गए दस्तावेज।
- एफआईआर दर्ज नहीं होने की स्थिति में उसका कारण।
- धान की कमी पूरी करने का आदेश।
- दोबारा स्टॉक सत्यापन रिपोर्ट।
- निलंबन आदेश और वर्तमान स्थिति।

शिवप्रसादनगर समिति

- साधना कुशवाहा के विरुद्ध मूल कार्रवाई आदेश।
- बर्खास्तगी आदेश, यदि जारी हुआ था।
- बहाली आदेश, यदि जारी हुआ था।
- वर्तमान निलंबन आदेश।
- कलेक्टर की संबंधित बैठकों की उपस्थिति सूची।
- बैठक में बुलाने का पत्र/अनुमति।
- समिति का प्रभार सौंपने संबंधी आदेश।

अब कलेक्टर से भी जवाब की उम्मीद

इस मामले में जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है,यदि साधना कुशवाहा निलंबित होने के बावजूद कलेक्टर की बैठकों में उपस्थित हुई हैं तो जिला प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए,कलेक्टर कार्यालय के पास बैठक की उपस्थिति का रिकॉर्ड होता है,इसी तरह संबंधित विभाग के पास निलंबन और बहाली के आदेश होने चाहिए,इसलिए सवाल का जवाब देना कठिन नहीं है।

क्षेत्रवासी कलेक्टर और मंत्री से मिलेंगे

मामले को लेकर क्षेत्रवासियों में नाराजगी की जानकारी सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि वे जल्द ही जिला कलेक्टर और संबंधित विभाग के मंत्री से मुलाकात कर सावारावां और शिवप्रसादनगर समितियों के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे,क्षेत्रवासियों की मांग है कि एफआईआर की स्थिति स्पष्ट हो,धान की कमी का पूरा हिसाब सामने आए,निलंबन और बहाली के आदेश सार्वजनिक किए जाएं तथा यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका नियम विरुद्ध पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए,अब सवाल दो समितियों का नहीं, व्यवस्था की विश्वसनीयता का है सावारावां में रिजवान के खिलाफ एफआईआर के लिए कागज चलने और ओड़गी शाखा प्रबंधक तक पहुंचने का दावा है, लेकिन एफआईआर दिखाई नहीं देती,सूत्र आरोप लगा रहे हैं कि कागज दबा दिया गया,वहीं शिवप्रसादनगर में साधना कुशवाहा का निलंबन बताया जा रहा है,लेकिन कलेक्टर की बैठकों में उनकी कथित उपस्थिति सवाल खड़े कर रही है,एक तरफ सवाल है...'रिजवान की एफआईआर का कागज कहां अटका?'दूसरी तरफ– 'साधना निलंबित हैं तो कलेक्टर की बैठक में कैसे पहुंचीं?' और तीसरा सवाल दोनों मामलों को जोड़ता है...सहकारिता विभाग में कार्रवाई वास्तव में नियम से हो रही है या फाइलों की गति के पीछे कोई और व्यवस्था काम कर रही है?

जिला अस्पताल सूरजपुर को मिली अस्थि रोग विशेषज्ञ की सौगात...डॉ. प्रसन्न मोहन त्रिपाठी की नियुक्ति,अब हड्डी एवं जोड़ संबंधी मरीजों को स्थानीय स्तर पर मिलेगी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा

-संवाददाता-

सूरजपुर,01 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जिला अस्पताल सूरजपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अस्थि रोग विशेषज्ञ के पद पर डॉ. प्रसन्न मोहन त्रिपाठी की नियुक्ति की गई है, उनकी पदस्थापना जिला अस्पताल सूरजपुर में की गई है,विशेषज्ञ चिकित्सक की उपलब्धता से अब हड्डी,जोड़ और मांसपेशियों से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को उपचार के लिए दूसरे बड़े शहरों या निजी अस्पतालों की ओर जाने की आवश्यकता कम होगी। जिला अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति को क्षेत्र के मरीजों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में देखा जा रहा है,सूरजपुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचते हैं,इनमें दुर्घटनाओं में घायल मरीजों के साथ-साथ हड्डी और जोड़ से संबंधित पुरानी बीमारियों से परेशान मरीज भी शामिल रहते हैं।

लंबे समय से महसूस की जा रही थी विशेषज्ञ की जरूरत-जिला

अस्पताल में अस्थि रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हड्डी से संबंधित कई मामलों में सामान्य चिकित्सकीय परामर्श के बजाय विशेषज्ञ जांच और उपचार की आवश्यकता होती है,सड़क दुर्घटनाओं, फ्रैक्चर, जोड़ संबंधी समस्याओं, हड्डियों में दर्द, चोट तथा अन्य ऑर्थोपेडिक समस्याओं के मरीजों को अक्सर विशेषज्ञ परामर्श के लिए रेफर किया जाता है,ऐसे मामलों में मरीज और उनके परिजनों को अतिरिक्त खर्च और समय के साथ दूसरे शहरों की यात्रा करनी पड़ती है। कई बार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह अतिरिक्त खर्च बड़ी परेशानी बन जाता है,अब जिला अस्पताल में अस्थि रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होने से ऐसे मरीजों को स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकीय सलाह और उपचार की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

दुर्घटना और फ्रैक्चर के मरीजों को होगा सीधा लाभ-सूरजपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में सड़क मार्गों से लगातार आवागमन होता है। दुर्घटनाओं के मामलों में फ्रैक्चर और अन्य हड्डी संबंधी चोटें आमतौर पर सामने आती हैं, ऐसे मरीजों के उपचार में समय महत्वपूर्ण होता है,विशेषज्ञ चिकित्सक की उपलब्धता से जिला अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों की प्रारंभिक जांच,उपचार की दिशा तय करने और आवश्यकता के अनुसार आगे की चिकित्सा प्रक्रिया निर्धारित करने में सुविधा होगी, इसके अलावा बुजुर्गों में हड्डियों से जुड़ी समस्याएं, जोड़ दर्द,चोट के बाद होने वाली जटिलताएं और लंबे समय से चली आ रही ऑर्थोपेडिक समस्याओं के मरीज भी विशेषज्ञ परामर्श का लाभ उठा सकेंगे।

सरकारी अस्पताल पर बढ़ेगा भरोसा-जिला अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इससे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत हो सकता है,अक्सर विशेषज्ञ सेवाओं की कमी के कारण मरीजों को निजी अस्पतालों या दूसरे जिलों के अस्पतालों में जाना पड़ता है, यदि जिला अस्पताल में विशेषज्ञ सेवाएं नियमित और प्रभावी रूप से उपलब्ध रहती हैं तो स्थानीय मरीजों को कम खर्च में उपचार मिलने की संभावना बढ़ेगी,साथ ही जिला अस्पताल पर आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा विकल्प भी उपलब्ध होंगे। विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि है,लेकिन इसका वास्तविक लाभ तभी मरीजों तक पहुंचेगा जब विशेषज्ञ सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हों।

- रसौकी में विकास के दावों की खुली तस्वीर
- मरीज को कंधे पर नदी पार, बाइक भी उठाकर ले गए ग्रामीण

पुल नहीं, तो बीमार को कंधे पर बैठाकर नदी पार कराने की मजबूरी

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के भटगांव विधानसभा क्षेत्र का मामला

पूर्व विधायक पारसनाथ राजवाड़े का दावा– 23.46 करोड़ की स्वीकृति के बावजूद काम रुका

बरसात में तीन जगह नदी पार करने को मजबूर ग्रामीण

रसौकी में विकास के दावों की खुली तस्वीर...मरीज को कंधे पर बैठाकर नदी पार कराया, बाइक भी ग्रामीणों ने उठाकर पहुंचाई दूसरी ओर

पूर्व विधायक पारसनाथ राजवाड़े का दावा...सड़क-पुल के लिए करोड़ों की स्वीकृति के बावजूद काम अधूरा...बरसात में तीन जगह नदी पार करने को मजबूर ग्रामीण...

-राजन पाण्डेय-

कोरिया/सूरजपुर,01 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में गांव-गांव तक सड़क,पुल और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के दावों के बीच सूरजपुर जिले के दूरस्थ रसौकी गांव से सामने आया एक वीडियो विकास की जमीनी तस्वीर पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है,वीडियो में एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीण उसे कंधे पर बैठाकर नदी पार कराते दिखाई दे रहे हैं,हालात इतने मुश्किल हैं कि मरीज को दूसरी तरफ ले जाने के बाद उसकी बाइक को भी ग्रामीणों ने कंधे पर उठाकर नदी पार कराई। यह तस्वीर केवल किसी एक परिवार की परेशानी नहीं,बल्कि बरसात के मौसम में रसौकी और आसपास के गांवों में रहने वाले ग्रामीणों की वर्षों पुरानी समस्या को सामने लाती है,पुल नहीं होने के कारण जब नदी का जलस्तर बढ़ता है तो सड़क और नदी के बीच का फर्क मिट जाता है और ग्रामीणों के लिए अस्पताल,स्कूल,बाजार और ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं रहता,हालिया रिपोर्टों में भी रसौकी के बरगा नदी के कारण बरसात में संपर्क बाधित होने और गांव के कई दिनों तक अलग-थलग पड़ने की स्थिति सामने आई है,अगस्त 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारी बारिश के दौरान रसौकी में कई दिनों तक आवागमन प्रभावित हुआ था और ग्रामीणों का तहसील व जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया था।

मरीज को अस्पताल ले जाना भी बन जाता है संघर्ष-ग्रामीणों के अनुसार हाल ही में गांव के एक व्यक्ति की तबीयत खराब हुई, उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत थी,लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ा होने के कारण वाहन सीधे दूसरी ओर नहीं जा सकता था,ऐसे में ग्रामीणों ने मरीज को कंधे पर बैठाया और पानी के बीच से नदी पार कराई,मरीज को नदी के दूसरी तरफ पहुंचाने के बाद उसकी बाइक भी ग्रामीणों ने उठाकर पार कराई,इसके बाद ही उसे वाहन के माध्यम से अस्पताल ले जाना संभव हुआ, यह दृश्य स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है,जिस क्षेत्र में किसी गंभीर मरीज के लिए हर मिनट महत्वपूर्ण होता है,वहां यदि पहले नदी पार कराने की व्यवस्था करनी पड़े तो आपातकालीन चिकित्सा सेवा कितनी प्रभावी हो पाएगी, यह सहज ही समझा जा सकता है।

30 किलोमीटर के रास्ते में अभी भी अधूरा सफर-ग्रामीणों के मुताबिक रसौकी से बिहारपुर की ओर जाने वाला मार्ग लगभग 30 किलोमीटर का है,इसमें करीब 20 किलोमीटर हिस्से में सड़क निर्माण हो चुका है,लेकिन शेष हिस्से में कच्चे रास्ते और नदी की बाधा अब भी बनी हुई है,हालांकि उपलब्ध सार्वजनिक सरकारी/समाचार रिकॉर्ड में बिहारपुर से रसौकी तक बारहमासी पक्की सड़क के लिए वर्ष 2023-24 में प्रशासनिक स्वीकृति और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम का उल्लेख मिलता है,जनवरी 2024 की रिपोर्ट में कहा गया था कि इस सड़क के बनने से निमडांड,अवंतिकापुर,उमझर,रसौकी सहित नौ गांवों के करीब 3778 ग्रामीणों को बारहमासी सड़क की सुविधा मिलनी थी और अस्पताल, ब्लॉक तथा जिला मुख्यालय तक पहुंच आसान होनी थी,लेकिन हालिया बारिश के दौरान रसौकी के संपर्क बाधित होने की खबरें यह संकेत देती हैं कि सड़क और पुल की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

23.46 करोड़ की स्वीकृति का दावा, फिर काम कहां अटका?-मामले में राजनीतिक सवाल भी अब सामने आ गया है, पूर्व भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े का दावा है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान उनके प्रयासों से रसौकी से नवाटोला तक करीब 12 किलोमीटर सड़क,पुल और पुलियों के निर्माण के लिए 23 करोड़ 46 लाख रुपये की स्वीकृति मिली थी,पूर्व विधायक का आरोप है कि सरकार बदलने के बाद काम रोक दिया गया और इसका खामियाजा आज ग्रामीण भुगत रहे हैं,हालांकि उपलब्ध ऑनलाइन रिकॉर्ड में 2022 के अनुपूरक बजट से जुड़े एक प्रकाशन में बिहारपुर-नावाटोला मुख्य मार्ग में रसौकी तक सड़क निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति का उल्लेख मिलता है, इसलिए 23.46 करोड़ रुपये की स्वीकृति संबंधी दावे की आधिकारिक स्वीकृति आदेश/कार्यादेश से अलग से पुष्टि किया जाना जरूरी है, यही वह बिंदु है जहां राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जाते हैं...स्वीकृति कितनी थी, किस योजना के तहत थी,किस हिस्से के लिए थी, टेंडर हुआ या नहीं, कार्यादेश जारी हुआ या नहीं और यदि कार्यादेश हुआ तो काम पूरा क्यों नहीं हुआ?

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विधानसभा क्षेत्र में उठे सवाल-रसौकी क्षेत्र भटगांव विधानसभा क्षेत्र में आता है,जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े करती हैं,ऐसे में इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक सवाल उठना स्वाभाविक है,लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कांग्रेस या भाजपा की राजनीति से ज्यादा अपने गांव की सड़क और पुल की चिंता है,उनका सीधा सवाल है...बरसात में यदि मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए कंधे का सहारा लेना पड़े तो विकास की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? उनकी मांग है कि सड़क और पुल का निर्माण राजनीतिक श्रेय का विषय न बनकर जनजीवन की आवश्यकता के रूप में देखा जाए।

सड़क-पुल का मतलब सिर्फ आवागमन नहीं-रसौकी जैसे दूरस्थ क्षेत्र में सड़क और पुल का निर्माण केवल वाहन चलाने की सुविधा नहीं देता,इसका सीधा संबंध स्वास्थ्य,शिक्षा,रोजगार,कृषि और आपातकालीन सेवाओं से है,सड़क नहीं होने का अर्थ है कि किसान अपनी उपज बाजार तक आसानी से नहीं पहुंचा पाएंगे,पुल नहीं होने का अर्थ है कि बरसात में बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे,और सबसे गंभीर स्थिति तब बनती है जब मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीणों को खुद मानव स्ट्रेचर बनना पड़े,यही वजह है कि वायरल वीडियो को केवल सोशल मीडिया का दृश्य मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता,यह उस क्षेत्र की कनेक्टिविटी की वास्तविक समस्या की ओर ध्यान खींचता है।

अब सरकार और प्रशासन से चाहिए स्पष्ट जवाब-रसौकी की समस्या पर अब सबसे जरूरी है कि प्रशासन मौके का निरीक्षण करे और सड़क-पुल परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करे, यदि 23.46 करोड़ रुपये की स्वीकृति का दावा सही है तो संबंधित स्वीकृति आदेश, कार्यादेश, टेंडर और वर्तमान स्थिति सार्वजनिक की जानी चाहिए,यदि राशि स्वीकृत होने के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ तो इसके कारण बताए जाने चाहिए,इसी तरह यदि बिहारपुर-रसौकी सड़क के लिए पूर्व में स्वीकृति और निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई थी,तो वर्तमान में वह किस चरण में है,इसका स्पष्ट जवाब ग्रामीणों को मिलना चाहिए,क्योंकि सवाल अब केवल रसौकी की सड़क का नहीं है,सवाल यह है कि जिस प्रदेश में विकास की योजनाओं और करोड़ों की स्वीकृतियों की घोषणा होती है, उसी प्रदेश के एक गांव में बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को उसे कंधे पर बैठाकर नदी क्यों पार करानी पड़ रही है? और जब नदी पार करने के बाद बाइक भी कंधे पर उठानी पड़े,तो यह तस्वीर किसी एक विभाग की नहीं,बल्कि सड़क,पुल,स्वास्थ्य और प्रशासनिक प्राथमिकताओं की पूरी व्यवस्था से जवाब मांगती है।

एंबुलेंस गांव तक पहुंचेगी कैसे?

ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में सड़क की स्थिति खराब होने के साथ नदी का जलस्तर बढ़ जाता है,ऐसे समय में 108 जैसी आपातकालीन सेवा के गांव तक पहुंचने में भी परेशानी होने की बात सामने आती है,यदि किसी गर्भवती महिला,बुजुर्ग या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को तत्काल अस्पताल ले जाना पड़े तो परिवार और ग्रामीणों को पहले नदी पार कराने की व्यवस्था करनी पड़ती है,यही कारण है कि ग्रामीणों की मांग केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है,वे चाहते हैं कि नदी पर स्थायी पुल बने,ताकि बारिश के दिनों में भी गांव का संपर्क बना रहे।

रसौकी-उमझर मार्ग बना सबसे बड़ी समस्या...

रसौकी क्षेत्र के ग्रामीणों के अनुसार रसौकी से उमझर के बीच बरंगा नदी कई स्थानों पर मार्ग को प्रभावित करती है,नदी के रास्ते और भूगोल के कारण बरसात में ग्रामीणों को अलग-अलग स्थानों से नदी पार करनी पड़ती है,सामाजिक कार्यकर्ता अवध यादव और ग्रामीण महेश यादव के अनुसार बरसात में ब्लॉक मुख्यालय की ओर जाने वाले रास्ते में ग्रामीणों को नदी को अलग-अलग स्थानों पर तीन बार तक पार करना पड़ता है,यानी सड़क केवल खराब नहीं है,बल्कि कई जगह नदी मार्ग को काट देती है,यही वजह है कि बरसात के दिनों में यह इलाका सामान्य ग्रामीण क्षेत्र के बजाय लगभग अलग-थलग क्षेत्र में बदल जाता है।

सरकार बदली तो क्या विकास कार्य भी बदल जाते हैं?

पूर्व विधायक पारसनाथ राजवाड़े का सवाल है कि यदि किसी सड़क और पुल के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई थी तो सरकार बदलने के बाद काम क्यों रोका गया,उनका तर्क है कि सरकारें बदलती रहती हैं,लेकिन सड़क और पुल किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं होते, ये जनता की जरूरत हैं,इसलिए यदि पूर्व सरकार के कार्यों को केवल राजनीतिक कारणों से रोका गया है तो इसका खामियाजा जनता को नहीं भुगतना चाहिए,यह आरोप राजनीतिक है और इसकी पुष्टि के लिए संबंधित विभाग से स्वीकृति,निविदा,कार्यादेश और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड सामने आना जरूरी है।

दूसरी ओर वर्तमान सरकार के विकास कार्यों का भी रिकॉर्ड मौजूद

यह भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भी सूरजपुर जिले में सड़क और पुल निर्माण के लिए स्वीकृतियां जारी हुई हैं,अगस्त 2025 में छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग ने सूरजपुर में सड़क और पुल निर्माण के लिए 26.03 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति की जानकारी दी थी,इसमें ओड़गी क्षेत्र के चोंगा से भोडवानीपारा-मौहारीपारा तक पुल-पुलियों सहित सड़क निर्माण के लिए 6.04 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति भी शामिल थी,इससे स्पष्ट है कि क्षेत्र में सड़क-पुल निर्माण के लिए सरकारी स्तर पर स्वीकृतियां जारी होती रही हैं,लेकिन रसौकी के ग्रामीणों का सवाल है कि उनके गांव तक स्थायी संपर्क कब पहुंचेगा।

पुलिसकर्मियों,डॉक्टरों और सफाई कर्मियों को राखी बांधकर जताया आभार रक्षाबंधन के बाद स्वच्छता दीदियों ने अशोक जायसवाल को राखी बांधी

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,01 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के पवित्र रिश्ते, स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बैकुंठपुर में इस पर्व को सामाजिक सरोकार और सेवा भावना से जोड़ते हुए कई भावनात्मक पहल देखने को मिलीं। एक ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र बहनों ने समाज की सुरक्षा,स्वास्थ्य और स्वच्छता में जुटे कर्मवीरों की कलाई पर राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका की स्वच्छता दीदियों ने रक्षाबंधन के उपरांत पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस कमेटी कोषाध्यक्ष अशोक जायसवाल को राखी बांधकर भाई-बहन के स्नेह का रिश्ता कायम किया।'एक राखी कर्तव्य को नमन' की भावना से अभाविप ने मनाया रक्षाबंधन...अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई बैकुंठपुर, जिला कोरिया के कार्यकर्ताओं ने रक्षाबंधन को समाजसेवा से जोड़ते हुए अनूठी पहल की, परिषद की छात्र बहनों ने पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों एवं सफाई कर्मियों की कलाई पर राखी बांधी और उनके कर्तव्य के प्रति सम्मान व्यक्त किया,इस पहल के पीछे परिषद की भावना थी कि समाज की सुरक्षा,स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए लगातार काम करने वाले ये कर्मवीर भी सम्मान और स्नेह के उतने ही अधिकारी हैं, जितना कोई पारिवारिक भाई,पुलिसकर्मी जहां दिन-रात लोगों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य पर तैनात रहते हैं, वहीं चिकित्सक मरीजों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी निभाते हैं, इसी तरह सफाई कर्मचारी शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन मेहनत करते हैं, कई बार इन कर्मवीरों को त्योहारों पर भी अपने परिवार से दूर रहकर ड्यूटी करनी पड़ती है,छात्र बहनों ने राखी बांधते हुए उनके योगदान के प्रति आभार जताया और कहा कि समाज की सेवा में समर्पित लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करना भी सामाजिक जिम्मेदारी है।

राखी बनी सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक-अभाविप की इस पहल ने रक्षाबंधन के पारंपरिक स्वरूप को सामाजिक सरोकार से जोड़ दिया,यहां राखी केवल भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं रही,बल्कि समाज की सुरक्षा और सेवा में लगे लोगों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति बनी, इस अवसर पर नगर मंत्री आयुषी साहू,माही,पंकज,जिला संयोजक बलबीर पुषाम सहित परिषद के अन्य कार्यकर्ता एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे,कार्यकर्ताओं ने कहा कि समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे परिवार का हिस्सा नहीं होते, लेकिन अपने कर्तव्य के माध्यम से पूरे समाज की जिम्मेदारी निभाते हैं, ऐसे लोगों को सम्मान देना और उनके योगदान को स्वीकार करना आवश्यक है।

80 स्वच्छता दीदियों ने अशोक जायसवाल को बांधी राखी-इसी क्रम में रक्षाबंधन के उपरांत बैकुंठपुर में एक और भावनात्मक दृश्य सामने आया,नगर पालिका में कार्यरत करीब 80 स्वच्छता दीदियों ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं जिला कांग्रेस कमेटी कोषाध्यक्ष अशोक जायसवाल को राखी बांधकर अपना स्नेह और सम्मान व्यक्त किया, स्वच्छता दीदियों ने बताया कि अशोक जायसवाल ने नगर के सफाई कर्मियों के हितों से जुड़े विषयों को हमेशा प्राथमिकता देने का प्रयास किया है,उनके अनुसार स्वच्छता साधनों की व्यवस्था से लेकर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान तक वे सफाई कर्मियों को परिवार का हिस्सा मानकर सहयोग करते रहे हैं, इसी अपनत्व और सहयोग की भावना के चलते स्वच्छता दीदियों ने उन्हें भाई मानकर राखी बांधने का निर्णय लिया।

राखी बांधने के बाद खिलाई मिठाई, दिए उपहार-स्वच्छता दीदियों द्वारा राखी बांधे जाने के बाद अशोक जायसवाल ने सभी को मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं और उपहार देकर उनका सम्मान किया, इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता दीदियां नगर की रीढ़ हैं,वे प्रतिदिन मेहनत कर शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं,उन्होंने कहा कि इन कर्मठ महिलाओं के प्रति सम्मान और अपनापन व्यक्त करना समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है,जायसवाल ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई-बहन के रिश्ते का त्योहार नहीं है,बल्कि यह विश्वास,सुरक्षा,स्नेह और आपसी जिम्मेदारी का प्रतीक भी है,स्वच्छता दीदियों ने जिस आत्मीयता के साथ उन्हें राखी बांधी है,उसे वे जीवनभर याद रखेंगे,उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भी सफाई कर्मियों के हितों से जुड़े विषयों के समाधान के लिए हरसंभव सहयोग किया जाएगा।

सेवा करने वालों को सम्मान देने का संदेश-बैकुंठपुर में रक्षाबंधन के दौरान सामने आई इन दोनों पहलों का संदेश अलग-अलग होते हुए भी एक ही भावना से जुड़ा नजर आया...जो समाज के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं,उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता, अभाविप की छात्र बहनों ने पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों और सफाई कर्मियों को राखी बांधकर समाज की सुरक्षा और सेवा में उनके योगदान को सम्मान दिया, तो नगर की स्वच्छता दीदियों ने अपने अनुभव और आत्मीयता के आधार पर अशोक जायसवाल को भाई मानकर राखी बांधी,इन आयोजनों ने यह संदेश भी दिया कि त्योहार केवल व्यक्तिगत खुशियों तक सीमित नहीं होते। यदि त्योहारों के माध्यम से समाज में सेवा,सम्मान,भाईचारा और आपसी विश्वास की भावना मजबूत होती है तो उसका प्रभाव कहीं व्यापक होता है, रक्षाबंधन के इस अवसर पर बैकुंठपुर में राखी की डोर ने जहां कर्तव्य निभाने वाले कर्मवीरों को सम्मान से जोड़ा, वहीं दूसरी ओर सामाजिक और जनसेवा के रिश्ते को भी भाई-बहन के स्नेह में बदलने का काम किया,लोगों ने इन पहलों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में अपनत्व और सकारात्मकता की भावना को मजबूत करते हैं।

हर साल जन्माष्टमी पर गली-मोहल्लों में शोर मचा रहा किशोर कुमार का गीत,सुनते ही झूम उठते हैं कृष्ण भक्त

रक्षाबंधन के बाद एक बार फिर से पूरा भारत फेस्टिवल के रंग में रंगने वाला है। 4 सितंबर को जन्माष्टमी आने वाली है, जहां हर और मंदिरों में इस त्यौहार को धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। अब त्यौहार का मौका हो और उसमें बॉलीवुड गानों का स्वाद न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आज हम आपको किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में गाए एक ऐसे गीत के बारे में बता रहे हैं, जो पिछले 44 सालों से जन्माष्टमी के फेस्टिवल की शान बना हुआ है। अमिताभ बच्चन का ये कल्ट गाना पूरी नगरी में रौनक ला देता है।

44 साल से जन्माष्टमी की जान है ये गीत

जन्माष्टमी स्पेशल जिस गाने का जिक्र हम इस लेख में कर रहे हैं, वह अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म है, जो इस खास मौके पर हर गली-मोहल्ले में बजता है और लोग झूम-झूमकर इस गाने पर डांस करते हैं। गाने के लिरिक्स हैं,मच गया शोर सारी नगरी में...आया बिरज का बांका संभाल अपनी गगरी रे। इस गाने में अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बाबी नजर आई थीं। 1984 में आई फिल्म खुद्दार में कान्हा जी की चंचलता को शब्दों के माध्यम से बयां करते इस गाने को किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज में गाया था। इसके लिरिक्स मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे। गाने का म्यूजिक राजेश रोशन ने दिया था।

यूट्यूब पर करोड़ों में मिले हैं कल्ट गाने को व्यूज

किसी गाने की लोकप्रियता का अगर अंदाजा लगाना है, तो आप उसके व्यूज से लगा सकते हैं। 4 अगस्त 2020 में यूट्यूब पर री-पोस्ट किए गए इस गीत को 1 करोड़ 91 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं। यह अमिताभ बच्चन के करियर के बेस्ट गानों में से एक है।

फिल्म खुद्दार की बात करें तो,मूवी में अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी के अलावा संजीव कुमार,राजू श्रेष्ठा,विनोद मेहरा,तनुजा,बिंदिया गोस्वामी,प्रेम चोपड़ा, महमूद, ए.के. हंगल जैसे एक्टर्स नजर आए थे। 1984 में आई खुद्दार ने बॉक्स ऑफिस पर 5 से 7 करोड़ का बिजनेस किया था। यह हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्मों में से एक है।

मुन्ना भैया और रवि किशन संग थिरकीं सोनल चौहान,रिलीज से पहले मिर्जापुर: द मूवी के हाई-वोल्टेज गाने घूम घूम की धूम

फिल्म मिर्जापुर: द मूवी का धमाकेदार गाना घूम घूम रिलीज हो गया है। 4 सितंबर 2026 को रिलीज हो रही इस फिल्म के इस हाई-एनर्जी ट्रैक में सोनल चौहान, दिव्येंदु और रवि किशन थिरकते नजर आ रहे हैं।ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपार सफलता और लोकप्रियता हासिल करने के बाद मिर्जापुर की खूंखार और रोमांचक दुनिया अब बड़े पर्दे पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के बैनर तले बनी बहुचर्चित फिल्म मिर्जापुर : द मूवी 4 सितंबर 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। सेंसर बोर्ड से फिल्म को ए सर्टिफिकेट भी मिल गया है। फिल्म की ग्रैंड रिलीज में अब बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है और दर्शकों के बीच उत्सुकता चरम पर है। इसी उत्साह को और बढ़ाने के लिए निर्माताओं ने फिल्म का नया हाई-वोल्टेज पार्टी ट्रैक घूम घूम जारी कर दिया है।

सोनल चौहान के सिजलिंग डांस और अभिनेताओं की जुगलबंदी ने बढ़ाई चमक

नए रिलीज हुए इस स्पेशल डांस नंबर में बॉलीवुड अभिनेत्री सोनल चौहान का बेहद ग्लैमरस और ऊर्जावान अवतार देखने को मिल रहा है। सोनल अपने सिजलिंग डांस स्टेप्स से स्क्रीन पर आग लगाती नजर आ रही हैं। उनका साथ दे रहे हैं फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता दिव्येंदु और रवि किशन, जो गाने में सोनल के साथ थिरकते हुए महफिल लूट रहे हैं। तीनों कलाकारों का यह अनोखा अंदाज और शानदार ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री इस गाने को एक परफेक्ट कमर्शियल चार्टबस्टर बनाती है।

राशमीत कौर की आवाज और कुमार के देसी बोल का जादू

संगीत की दृष्टि से घूम घूम गाना हर किसी को झूमने पर मजबूर कर देने वाला ट्रैक है। इस धमाकेदार गाने को मशहूर गायिका राशमीत कौर और संगीतकार रे ने अपनी आवाज से सजाया है। गाने का कैची म्यूजिक रे द्वारा ही तैयार किया गया है,जबकि इसके ऊर्जावान बोल जाने-माने गीतकार कुमार ने लिखे हैं। जैसे ही मेकर्स ने सोशल मीडिया पर गाने को शेयर करते हुए 4 सितंबर की रिलीज का रिमाइंडर दिया,वैसे ही यह ट्रैक म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया रील्स पर ट्रेंड करने लगा।

4 सितंबर को बड़े पर्दे पर दिखेगा मिर्जापुर का नया और अनकहा रूप

निर्देशक गुरमीत सिंह और लेखक पुनीत कृष्णा की यह फिल्म वेब सीरीज के प्रशंसकों के लिए एक बिल्कुल नया और अनूठा अनुभव लेकर आ रही है। इस थिएट्रिकल वर्जन में पंकज त्रिपाठी,अली फजल और दिव्येंदु मुख्य आकर्षण होंगे। इसके अलावा,रसिका दुग्गल,श्वेता त्रिपाठी,अभिषेक बनर्जी,राजेश तैलंग,शीबा चड्ढा,प्रमोद पाठक,श्रिया पिलगांवकर और मोहित मलिक जैसे अनुभवी कलाकारों की फौज भी सिनेमाघरों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरती नजर आएगी। रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म 4 सितंबर को हिंदी और तेलुगु भाषाओं में रिलीज की जाएगी।

सैयारा के बाद हुंकार भरने को तैयार अनीत पड्डा

जारी हुआ नई फिल्म का टीजर, बेखौफ अंदाज में नजर आई एक्ट्रेस

मेकर्स ने हुंकार : द रोर का टीजर जारी कर दिया है। टीजर में अनीत पड्डा की झलक देखने को मिलती है, जिनका किरदार एक आरोप सत्ता,सच्चाई और न्याय से जुड़ी एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत करता है। सैयारा की वाणी यानी अनीत पड्डा अब एक नए और बिलकुल अलग अवतार में नजर आने वाली हैं। अनीत नई ड्रामा सीरीज हुंकार : द रोर में नजर आने वाली हैं, जिसका टीजर जारी किया जा चुका है। यह सीरीज एक ऐसे आरोप के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक ताकतवर सिस्टम को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है। कहानी 17 साल की मीनू रावत के इर्द-गिर्द घूमती है,जिसका किरदार अनीत पड्डा निभा रही हैं। मीनू बापजी के नाम से मशहूर जाने-माने कल्ट लीडर सुनील चाकोसी पर एक आरोप लगाती है, जिसके बाद बापजी के खिलाफ बड़ी जांच शुरू हो जाती है। टीजर से साफ है कि एक आरोप से शुरू होने वाली कहानी जल्दी ही एक बड़ी लड़ाई में बदल जाती है और मामला पुलिस के बाद कोर्ट और मीडिया तक पहुंचता है और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है।

सितंबर का खास आगाज:एक्टर नानी ने दिखाई अपनी छोटी सी जन्नत

तेलुगु स्टार नानी ने अपने छोटे बेटे अर्जुन के साथ कुछ खास पल शेयर करते हुए और अपनी छोटी सी दुनिया की एक प्यारी सी झलक दिखाते हुए सितंबर का स्वागत किया। नानी ने जिम से कुछ ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनके बेटे अर्जुन के साथ प्यारे पल कैद हैं।

बाप-बेटे की जोड़ी को मस्ती भरे अंदाज़ में आर्म-रेसलिंग (हाथों से कुश्ती) करते हुए देखा जा सकता है, जबकि एक दूसरी तस्वीर में उनके बेटे की बनाई हुई एक ड्राइंग दिखाई दे रही है। नानी की शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंजना येलावरथी से हुई है। उन्होंने 2012 में शादी की थी। इस कपल के घर 2017 में बेटे का जन्म हुआ। नानी की अगली फिल्म द पैराडाइज़ है। इस फिल्म को एसएलवी सिनेमाज़ बना रहा है और इसे पहले 26 मार्च, 2026 को बड़े पैमाने पर रिलीज़ किया जाना था। अब फिल्म की रिलीज़ की तारीख 24 सितंबर है। इस फिल्म को लेकर फैंस और फिल्म प्रेमियों में काफी उम्मीदें हैं और टीज़र ने इस उत्साह को और बढ़ा दिया है। उम्मीद है कि यह फिल्म आठ भाषाओं - हिंदी,तेलुगु,तमिल,अंग्रेजी,स्पेनिश,बंगाली,कन्नड़ और मलयालम-में रिलीज़ होगी। नानी सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले और सबसे लोकप्रिय भारतीय अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने 2008 में रोमांटिक कॉमेडी अष्टा चम्मा से डेब्यू किया,जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही,और 2011 में अला मोदलाइनडी से उन्हें बड़ी पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने पिल्ला ज़मींदार,ईगा और येवाडे सुब्रमण्यम जैसी कमर्शियल रूप से सफल फिल्मों में काम किया और अपने करियर को और मज़बूत किया। उन्होंने 2012 में येतो वेल्लीपोयिंधी मनसु के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नंदी पुरस्कार जीता। नानी ने भले भले मगदिवॉय, कृष्णा गादी वीरा प्रेमा गाधा, जेंटलमैन, नेनु लोकल, निन्नु कोरी,मिडल क्लास अब्बायि,जर्सी,नानीज़ गैंग लीडर,श्याम सिंघा रॉय,अंटे सुंदरानिकी, दसारा, हाय नाना, सरिपोधा सनिवारम और एचआईटी : द थर्ड केस जैसी फिल्मों से सफलता हासिल की।

मालविका मोहनन का सरदार 2 पर बड़ा बयान: पहले ही दिन स्टंट से डर गई थी

एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने सरदार 2 की शूटिंग के अपने अनुभव के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि सेट पर उनका पहला दिन एक मुश्किल स्टंट सीन के साथ शुरू हुआ। एक्ट्रेस ने याद करते हुए बताया कि उन्हें एक एक्शन सीन के हिस्से के तौर पर 100-150 मीटर की बड़ी छलांग लगाने के लिए कहा गया था। उन्होंने इसे शूटिंग के सबसे डरावने पहले दिनों में से एक बताया। सरदार 2 के ऑडियो लॉन्च पर,मालविका ने फिल्म की शूटिंग के दौरान आए सबसे मुश्किल अनुभवों में से एक के बारे में बात की। सेट पर अपने पहले दिन को याद करते हुए...उन्होंने कहा,शूटिंग के पहले दिन मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मेरा पहला दिन एक स्टंट सीन था,और मुझे, मुझे लगता है, 100-150 मीटर से कूदना था और यह एक फ्री फॉल जैसा था। हमारे पास रस्सियाँ और बाकी चीज़ें थीं। लेकिन यह एक बहुत बड़ी छलांग थी, और मुझे लगता है कि किसी भी सेट पर शूटिंग का यह मेरा सबसे डरावना पहला दिन था। सरदार 2,जिसे पी.एस. मित्रन ने डायरेक्ट किया है, में कार्थी भी हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, हो सकता है कि आप प्लास्टिक की पानी की बोतलों से पानी पीने की आदत जारी रखे हों, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद,आप उस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर पाएँगे जो यह फिल्म कहना चाहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने एक ऐसे सच के बारे में बात की है जो आपकी सेहत से जुड़ा है, और वह मुद्दा आपको ज़रूर झकझोर देगा। डायरेक्टर पी.एस. मित्रन और कार्थी ने कहा,हो सकता है कि आप प्लास्टिक की पानी की बोतलों से पानी पीने की आदत जारी रखे हों,लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद, आप उस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर पाएँगे जो यह फिल्म कहना चाहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने एक ऐसे सच के बारे में बात की है जो आपकी सेहत से जुड़ा है,और वह मुद्दा आपको ज़रूर झकझोर देगा।

खेल समाचार

भारत बनाम अफगानिस्तान टी 20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन को भी मिली जगह

नई दिल्ली,01 सितम्बर 2026। भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान बीसीसीआई की ओर से कर दिया गया है। सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर में ही तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इसका पहला मुकाबला 13 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इस बीच बीसीसीआई की ओर से टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान एक बार फिर से श्रेयस अय्यर के ही पास रहेगी। खास बात ये है कि जहां एक ओर वैभव सूर्यवंशी को टीम में जगह मिली है, वहीं संजू सैमसन की एक बार फिर से वापसी हो गई है।

चार खिलाड़ियों के आगे लगा है स्टार का निशान

इस बीच खास बात ये है कि जो टीम बीसीसीआई ने चुनी है, उसमें से चार के आगे

स्टार लगा है। यानी अगर वे फिट होंगे, तभी खेल पाएंगे। इसमें नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा का नाम शामिल है। ये सभी खिलाड़ी पिछले कुछ वक्त से चोटिल थे। यानी अभी तक उनकी फिटनेस पर आखिरी अपडेट नहीं आया है।

अफगानिस्तान है सीरीज का होस्ट

सीरीज के सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे, लेकिन इसकी मेजबानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी एसीबी कर रहा है। पहला मैच जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि 13 सितंबर को है, इसके बाद दूसरा मैच 15 और तीसरा 17 सितंबर को खेला जाएगा। अफगानिस्तान की ओर से पहले ही स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। जल्द ही टीम यहां आकर अपनी तैयारी शुरू कर देगी।

जिम्बाब्वे सीरीज से बाहर हो गए थे संजू सैमसन

इससे पहले उस वक्त बीसीसीआई को जबरदस्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, जब संजू सैमसन को अचानक जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब उनकी वापसी हो चुकी है। अब टीम में फिर से तीन ओपनर हो गए हैं। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के अलावा संजू भी हैं। यानी मैच में एक सलामी बल्लेबाज को बाहर बैठना पड़ेगा, ये करीब करीब तय है।

भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का स्क्वाडः श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा।

पाकिस्तान क्रिकेट में नया बवाल

इमाम और रिजवान के चयन पर सिलेक्टर्स को पीसीबी का कारण बताओ नोटिस

लाहौर,01 सितम्बर 2026। पाकिस्तान क्रिकेट में इन दिनों उथल-पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। इंग्लैंड दौरे के बीच टीम में बड़े पैमाने पर बदलाव करने के

बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने अपने ही सिलेक्टर्स से जवाब मांग लिया है। बोर्ड ने इमाम-उल-हक और मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।मिली जानकारी के अनुसार,पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों से इमाम और रिजवान के चयन के पीछे की पूरी वजह स्पष्ट करने को कहा है। सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद,मिस्बाह-उल-हक, सरफराज अहमद और असद शफीक जैसे पूर्व खिलाड़ी शामिल हैं। सभी सदस्यों को जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। पीसीबी के एक प्रवक्ता ने 1 सितंबर की शाम सिलेक्शन कमेटी को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि की। बोर्ड के मुख्य परिचालन अधिकारी समीर अहमद की ओर से जारी एक पेज के नोटिस में सिलेक्टर्स से पूछा गया है कि इन दोनों खिलाड़ियों को चुनने का आधार क्या था। बोर्ड ने चयन मानदंड,खिलाड़ियों के प्रदर्शन और चयन के दौरान ध्यान में रखे गए अन्य पहलुओं की जानकारी भी मांगी है।

हेटमायर ने टी 20 क्रिकेट में पूरे किए 7000 रन

पोर्ट ऑफ स्पेन,01 सितम्बर 2026। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर ने मंगलवार को टी 20 क्रिकेट में 7,000 रन पूरे किए। इसके बाद उन्होंने नाबाद 111 रन की पारी खेलकर गयाना अमेज़न वॉरियर्स को कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 के बारिश से प्रभावित मैच में

ट्रिनबागो नाइट राइडर्स पर नौ रन से जीत दिलाई। हेटमायर टी 20 क्रिकेट (सबसे छोटे फॉर्मेट) में 7,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले नए बल्लेबाज बन गए हैं। उनकी यह मैच जिताने वाली पारी सिर्फ 43 गेंदों की थी, जिसमें आठ चौके और नौ छक्के शामिल थे। 29 वर्षीय हेटमायर के नाम अब 352 टी 20 मैचों में 26.67 की औसत और 145.05 के स्ट्राइक रेट से 7,096 रन हैं। उनके नाम दो शतक और 35 अर्धशतक हैं, साथ ही उन्होंने 485 चौके और 413 छक्के लगाए हैं। उनकी नाबाद 111 रन की पारी टी 20 क्रिकेट में उनका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी है। मैच को प्रति टीम 16 ओवर का कर दिया गया था और अमेज़न वॉरियर्स का स्कोर 19 रन पर दो विकेट था, जब हेटमायर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने शानदार जवाबी हमला किया। उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर 40 गेंदों में शतक तक पहुंचे।

मिस्बाह उल हक ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली,01 सितम्बर 2026। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिसबाह-उल-हक ने पाकिस्तान पुरुष राष्ट्रीय चयन समिति से इस्तीफ़ा दे दिया है। यह

फ़ैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा इंग्लैंड के मौजूदा दौरे के दौरान टेस्ट टीम और कोचिंग स्टाफ़ में बड़े बदलाव करने के बाद लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार,पीसीबी ने अभी तक मिसबाह का इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने लाहौर में नेशनल क्रिकेट अकादमी में बैटिंग कंसल्टेंट की भूमिका से भी हटने का फ़ैसला किया है।

नाम परिवर्तन सूचना

मै राकेश कुमार गुप्ता पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता उम्र 41 वर्ष निवासी- रिंग रोड बौरीपारा, अम्बिकापुर थाना व तह अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 । यह कि मेरी पुत्री परी गुप्ता (PARI GUPTA) का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसका जन्म तिथि 08.05.2019 है। उक्त जन्म प्रमाण पत्र में मेरी पुत्री का घरेलु नाम परी गुप्ता त्रुटिवश दर्ज हो गया है जबकी मेरी पुत्री का वास्तविक नाम यश्विका गुप्ता (YASHVIKA GUPTA) है जिसे मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज नाम परी गुप्ता को विलोपित कर यश्विका गुप्ता (YASHVIKA GUPTA) दर्ज चाहता हूँ जिसके संबंध में स्वयं का शपथ पत्र निष्पादित कर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

शपथग्रहिता
राकेश कुमार गुप्ता

नाम परिवर्तन सूचना

प्ररूप-(एक)

मै आकाश कुमार राजवाड़े (पुराना नाम,जिसे बदला जाना है) सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी राधा कान्त राजवाड़े गांव/शहर कतकालो तहसील दरिमा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ ने अपना नाम आकाश कुमार राजवाड़े (पुराना नाम) से बदल कर आकाशदीप राजवाड़े (नया नाम) रख लिया है।

आवेदक
आकाश कुमार राजवाड़े
कतकालो तहसील दरिमा-जिला सरगुजा छत्तीसगढ़

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी,रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर,छत्तीसगढ़

ईश्तहार

रा.प्र.क्र...ब-121/2025-26

आम जनता ग्रामवासी ग्राम केशवपुर को सूचित किया जाता है कि श्री धर्मजीत आ0 श्री रतन जाति गोंड़ निवासी ग्राम केशवपुर थाना तहसील रामानुजनगर जिला-सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा अपने बाबा विकुल राम आ0 कारी का मृत्यु दिनांक 30/09/2014 के होने से मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसपर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

जिस किसी आम जनता /ग्रामवासियो को कोई आपत्ति/आक्षेप हो तो वह अपना आपत्ति दिनाँक 03/09/2026 को इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है, नियत तिथि के पश्चात् कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

आज दिनांक 06/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मद मुद्रा से जारी किया गया है।

तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी
सील **रामानुजनगर,जिला-सूरजपुर**

छत्तीसगढ़ शासन,जल संसाधन विभाग

कार्यालय कार्यपालन अभियंता

जल संसाधन संभाग क्र-2,रामानुजगंज,जिला-बलरामपुर-रा0ग0

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

eProcurement Portal:https://eproc.cgstate.gov.in

(प्रथम आमंत्रण)

निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक 17.09.2026 समय 17:30 तक ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैः-

स.क्र.	निविदा सूचना क्रमांक	सिस्टम निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	निविदा की लागत जी.एस.टी. छोड़कर (लाख में)	आमंत्रण क्रमांक
1	198315	04/.ले.नि./2026-27, दिनांक 27.08.2026	शिरवानी एनीकट योजना का निर्माण कार्य ।	राशि रु. 293.13 लाख	प्रथम आमंत्रण

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 03.09.2026 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते है।

नोटः-1. निविदा मे भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है ।

2.निविदा की अनुमानित लागत एस. ओ. आर. दिनांक 01.05.2025 एवं दिनांक 08.08.2025 के जारी संशोधन के अनुसार है।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज
(छ.ग.) कृते - मुख्य अभियंता
हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग
अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

जी0नं0 -262703021/5

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगॉव तहसील भैयाथान

// ईश्तहार //

रा0प्र0क्र02-121/20

आम जनता ग्राम धरतीपारा को सूचित किया जाता है कि सूचित किया जाता आवेदक/आवेदक भोला शंकर प्रजापतिऑ0 स्व सखाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम धरतीपारा तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर द्वारा अपने पुत्र/पुत्री / पिता/माता मंगली का जन्म/मृत्यु दिनांक 22/04/2008 को जन्म/मृत्यु होने पर आवेदक द्वारा अपने पुत्र / पुत्री / माता / पिता का जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत शुल्क अदा कर चालान की प्रति,शपथ पत्र अनुपलब्धतां प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्यवाही प्रारंभ कर दी. गयी है।

जिस किसी हितबद्ध पक्षकार को कोई आक्षेप हो तो वह अपना आक्षेप दिनांक..14/09/2026 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी । आज दिनांक 31/08/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील
कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भटगांव
जिला-सूरजपुर(छ0ग0)

जस्टिस कृष्णा राम मोहपात्रा होंगे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नए चीफ जस्टिस

रमेश सिन्हा 4 सितंबर को रिटायर हो रहे,संजय अग्रवाल बनेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस

बिलासपुर,01 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की जगह अब ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा राम मोहपात्रा नए चीफ जस्टिस होंगे। वहीं,छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दोनों की नियुक्ति की अनुशंसा की है। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा 4 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। वहीं, कॉलेजियम ने जस्टिस संजय के. अग्रवाल के साथ ही गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस अल्पेश यशवंत कागजी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा की है।

हाईकोर्ट में होंगे कई बदलाव

कॉलेजियम ने ओडिशा हाईकोर्ट के 2 जजों के तबादले की भी सिफारिश की है। जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा का तबादला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट किया गया है। साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा की गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के जस्टिस संजय अग्रवाल को प्रमोशन देकर राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति की भी अनुशंसा की है। इनमें बेंच कोटे से तीन न्यायिक अधिकारी संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार शामिल हैं। इनकी नियुक्ति के बाद हाईकोर्ट में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं, हाईकोर्ट के सीनियर जज संजय के. अग्रवाल के प्रमोशन के बाद राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने की अनुशंसा की गई है। ऐसे में हाईकोर्ट में एक सीनियर जज कम हो जाएंगे। जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा का जन्म 18 अप्रैल 1965 को हुआ था। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी न्यायिक रही है। उनके पिता सरत चंद्र मोहपात्रा जज रह चुके हैं। जस्टिस मोहपात्रा ने बीए और एलएलबी की शिक्षा हासिल की है। उन्होंने 7 फरवरी 1988 को ओडिशा स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया था।

कई कानूनी क्षेत्रों का है अनुभव

जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा को अभिभावक और आश्रित अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक-संरक्षकता अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण,भरण-पोषण अधिनियम और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम से जुड़े मामलों का भी अनुभव रहा है। उन्होंने ओडिशा सरकार के साथ-साथ ओडिशा लोक सेवा आयोग के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा, वे अलग-अलग सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों से जुड़े मामलों में अधिवक्ता के रूप में पैरवी कर चुके हैं।

वकालत के दौरान उन्होंने कानून की कई शाखाओं में काम किया। सिविल,सेवा, आपराधिक और संवैधानिक मामलों समेत अलग-अलग क्षेत्रों में उन्हें करीब 26 साल का अनुभव रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने 3 हाईकोर्ट जजों को प्रमोशन देकर चीफ जस्टिस बनाने की भी सिफारिश की है। इसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा की गई है। साथ ही गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस अल्पेश यशवंत कोग्जे को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा की गई है।

छत्तीसगढ़ पीडब्ल्यूडी में 56 इंजीनियरों का तबादला

रायपुर से लेकर बस्तर-सरगुजा तक बदली पदस्थापना

रायपुर,01 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विभाग ने 56 कार्यपालन अभियंताओं (सिविल) की पदस्थापना में बदलाव करते हुए तबादला आदेश जारी किया है। आदेश 1 सितंबर 2026 को जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार इंजीनियरों को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित कर तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। तबादलों में रायपुर,बिलासपुर,दुर्ग, राजनांदगांव,रायगढ़,जांजगीर-चांपा, बस्तर,दंतेवाड़ा, सुकमा,बीजापुर,कांकेर,नारायणपुर,सरगुजा,जशपुर, कोरबा समेत कई क्षेत्रों के पीडब्ल्यूडी कार्यालय और संभाग शामिल हैं।

कई अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

तबादला सूची में नियमित कार्यपालन अभियंताओं के साथ ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं,जिन्हें पदोन्नति के बाद कार्यपालन अभियंता के पद पर नई पदस्थापना दी गई है। कई अधिकारियों को संभाग,सेतु संभाग और क्षेत्रीय कार्यालयों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

रायपुर से बस्तर और सरगुजा तक फेरबदल

आदेश में राजधानी रायपुर के अलावा बिलासपुर, खैरागढ़,मोहला,राजनांदगांव,बालोद,कवर्धा, महासमुंद,बेमेतरा,दंतेवाड़ा,कांकेर,कोंडागांव, नारायणपुर,जशपुर,मनेन्द्रगढ़,रामानुजगंज, अंबिकापुर,रायगढ़ और अन्य संभागों में अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई है।

तत्काल प्रभाव से लागू होगा आदेश

विभाग के आदेश में कहा गया है कि स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है और संबंधित अधिकारियों को आदेश के अनुसार नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। तबादला आदेश की प्रतिलिपि संबंधित प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कलेक्टरों को भी भेजी गई है।

छत्तीसगढ़ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी-तीज पर छुट्टी

4 रविवार और 2 शनिवार समेत 6 दिन बैंक बंद रहेंगे

रायपुर,01 सितम्बर 2026। सितंबर का महीना छुट्टियों के लिहाज से खास रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और 14 सितंबर को हरितालिका तीज पर शासकीय अवकाश रहेगा। इन दो दिन स्कूल-कॉलेज और शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। वहीं, सितंबर में रविवार और शनिवार की छुट्टियों के साथ बैंक और शेयर बाजार के लिए भी अलग-अलग छुट्टियां रहेंगी। इसलिए जरूरी काम समय पर पहले निपटा लें।

3 दिन लगातार अवकाश

छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2026 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर शासकीय अवकाश रहेगा। इसके बाद 5 सितंबर शनिवार और 6 सितंबर रविवार होने के कारण लगातार छुट्टी का मौका भी मिलेगा। ऐसे में 2 दिनलगातार 3 दिन सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इसके बाद 14 सितंबर को हरितालिका तीज पर शासकीय अवकाश रहेगा। छत्तीसगढ़ में तीज का खास महत्व है। इस दिन सरकारी दफ्तरों के साथ स्कूल-कॉलेजों में भी छुट्टी रहेगी।

15 सितंबर को नुआखाई का स्थानीय अवकाश

15 सितंबर को नुआखाई पर्व पर स्थानीय अवकाश का प्रावधान है। यह छुट्टी जिले के हिसाब से लागू होगी। इसलिए संबंधित जिले के स्थानीय अवकाश आदेश के आधार पर इसकी पुष्टि की जा सकेगी। सितंबर में हरछठ, पोला, गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा जयंती, नवाखाई, ढोल ग्यारस और अनंत चतुर्दशी जैसे पर्वों पर ऐच्छिक अवकाश का भी प्रावधान है।

दूसरे और चौथे शनिवार के साथ रविवार की छुट्टी : सितंबर में बैंक 12 सितंबर (दूसरा शनिवार) और 26 सितंबर (चौथा शनिवार) को देशभर में बंद रहेंगे। इसके अलावा 6, 13, 20 और 27 सितंबर को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको इस महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में साय सरकार का बड़ा फैसला,प्रदेश में खुलेंगे 354 नए धान खरीदी केंद्र

रायपुर,01 सितम्बर 2026। किसानों को धान बेचने के लिए दूर-दराज के उपार्जन केंद्रों तक जाने की परेशानी से राहत मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 और आगामी खरीफ विपणन वर्षों के लिए प्रदेश में 354 नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की अनुमति दी है। खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल के नेतृत्व में विभाग की ओर से यह निर्णय किसानों को उनके क्षेत्र के नजदीक धान बेचने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। नए केंद्र शुरू होने के बाद किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे परिवहन का खर्च और समय दोनों बचने की उम्मीद है। सरकार ने नवीन केंद्रों के चयन में किसानों की सुविधा और केंद्र तक उनकी सुगम पहुंच को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।

बेमेतरा जिले में कई नए केंद्र स्वीकृत: 354 नए धान उपार्जन केंद्रों की स्वीकृति का लाभ बेमेतरा जिले को भी मिला है। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में पिपरिया, कंदई,सांकरा,भाठासोरही,गांगपुर,लालपुर, बटार,करचुवा,मजगवां,एरमशाही और तेंदू सहित कई स्थानों पर नवीन धान उपार्जन केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। वहीं नवागढ़ क्षेत्र के किसानों के लिए भी कई नए केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इनमें पुटपुरा,ठेंगा भाठ,बाघुल, नांदल, गाड़ामोर और तोरा सहित अन्य स्थान शामिल हैं।

केंद्रों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश : सरकार की ओर से जारी आदेश में नए धान खरीदी केंद्रों के चयन और संचालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। जहां मंडी या उपमंडी के प्रांगण उपलब्ध हैं, वहां उनका उपयोग धान खरीदी के लिए करने को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसके अलावा केंद्रों पर पर्याप्त समतल और ऊंची भूमि, धान के सुरक्षित रख-रखाव के लिए पर्याप्त जगह और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों की सुविधा को देखते हुए केंद्रों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली और प्रकाश,पेयजल तथा आवागमन के लिए उचित रास्ते की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया है।

धान खरीदी व्यवस्था को किसान-केंद्रित बनाने पर जोर

राज्य सरकार का कहना है कि नए केंद्रों के खुलने से धान खरीदी की व्यवस्था अधिक सुलभ होगी और किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय को सरकार की किसान-केंद्रित व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए उपार्जन केंद्रों की स्वीकृति से विशेष रूप से उन क्षेत्रों के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है,जहां अब तक धान बेचने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत दूर स्थित केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता था। किसानों ने भी नजदीकी स्तर पर धान खरीदी की सुविधा बढ़ाने के इस निर्णय का स्वागत किया है।

छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा बने सीनियर एडवोकेट,हाईकोर्ट ने दी मंजूरी

बिलासपुर,01 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा को हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया है। हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने आज इस पर अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना के मुताबिक, विवेक शर्मा का सीनियर एडवोकेट के रूप में पदनाम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के 13 मई 2025 के फैसले और आदेश का भी उल्लेख किया गया है। यह आदेश आपराधिक अपील संख्या 865 of 2025, जितेंदर कल्ला बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) मामले में पारित हुआ था। इसी के अनुपालन में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने विवेक शर्मा को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने का निर्णय लिया।

124 करोड़ के दमकल-गाड़ियों की खरीदी का रास्ता साफ

हाईकोर्ट के दखल पर वित्त सचिव ने दिया शपथपत्र, 31 मार्च तक बढ़ी खरीदी की समय-सीमा

बिलासपुर,01 सितम्बर 2026। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दमकल गाड़ियों की खरीदी के लिए खर्च की समय-सीमा बढ़ाने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट के इस हस्तक्षेप के बाद प्रदेश में 124 करोड़ रुपए की लागत से अग्निशमन वाहनों की खरीदी का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को यह जानकारी वित्त सचिव के शपथ पत्र के जरिए हाईकोर्ट में दी गई। इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका की लगातार सुनवाई चल रही है। 19 अगस्त को चीफ जस्टिस की डीविजन बेंच ने राज्य शासन की लेटलतीफी और प्रक्रिया में देरी पर नाराजगी जताई थी। इसके साथ ही वित्त सचिव से शपथपत्र मांगा गया था। जिस पर सोमवार को वित्त सचिव ने शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि अग्निशमन वाहनों की खरीदी के लिए निर्धारित राशि खर्च करने की समय सीमा टेंडर प्रक्रिया में हुई देरी के कारण समाप्त हो गई थी। इसके चलते समय सीमा बढ़ाना जरूरी था। वित्त सचिव ने अब यह अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है। इससे करीब 6 महीने से लंबित खरीदी प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। वाहनों की खरीदी के लिए टेंडर सहित अन्य प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और मामला अंतिम चरण में है। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने डिवीजन बेंच को इसकी जानकारी दी।

छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला मामला : आरती वासनिक और ललित गनवीर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

रायपुर,01 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला मामले में गिरफ्तार तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी। वराले की पीठ ने की। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरती वासनिक और पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक ललित गनवीर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। नएस्थान तलाशें

कोर्ट में बचाव पक्ष ने क्या बताया?

सर्वोच्च न्यायलय में आरती वासनिक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी.बी. सुरेश के साथ अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि आरती वासनिक एक वर्ष से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और मुकदमे के दौरान 100 से अधिक गवाहों का परीक्षण किया जाना है। यह भी तर्क दिया गया कि मुकदमे में देरी अभियुक्त की वजह से नहीं, बल्कि अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हो रही है।

बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से आरती वासनिक की किसी प्रत्यक्ष भूमिका का आरोप नहीं लगाया गया है। साथ ही कथित तौर पर मामले से लाभान्वित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां फिलहाल स्थगित होने की जानकारी भी दी गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरती वासनिक और ललित गनवीर को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। सीजीपीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोगकी भर्ती प्रक्रिया में 2020 से 2022 के बीच हुई अनियमितताओं से जुड़ा मामला है। आरोप है कि इस दौरान आयोजित परीक्षाओं और साक्षात्कारों में योग्य अभ्यर्थियों की उपेक्षा कर, प्रभावशाली राजनेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के करीबियों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी तथा अन्य उच्च पदों पर चयनित किया गया। इस घोटाले ने प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई। जांच एजेंसी ने छापेमारी कर कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद किए और पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया। वर्तमान में यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में है।

अफीम-केस में पूर्व भाजपा नेता को मिली हाईकोर्ट से जमानत...कोर्ट बोला-खेत में मौजूद नहीं था विनायक

ताम्रकार,कब्जे से नशीला पदार्थ भी नहीं मिला

दुर्ग-भिलाई,01 सितम्बर 2026। दुर्ग जिले में करीब 5 एकड़ में अफीम की अवैध खेती के चर्चित मामले में पूर्व भाजपा नेता विनायक ताम्रकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की कोर्ट ने मंगलवार को विनायक की जमानत मंजूर कर दी। कोर्ट ने माना कि घटना के समय विनायक खेत में मौजूद नहीं था। उसके कब्जे से कोई नशीला पदार्थ भी बरामद नहीं हुआ है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है और 29 जुलाई को आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। पुलगांव थाना क्षेत्र के समोद गांव में 6 मार्च को पुलिस ने करीब पांच एकड़ कृषि भूमि पर अफीम की अवैध खेती पकड़ी थी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस, राजस्व, आबकारी, नारकोटिक्स नियंत्रण और जांच टीम के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। टीम को खसरा नंबर 309 और 310 में बड़ी संख्या में अफीम के पौधे मिले थे। मौके से सह आरोपी विकास बिश्नोई को पकड़ा गया था। जांच में सामने आया कि जिस जमीन पर खेती मिली, वह मधुमति ताम्रकार और प्रीतिबाला ताम्रकार के नाम पर दर्ज है। अभियोजन की ओर से विनायक ताम्रकार को मामले से जोड़ने के लिए खेत में मौजूद पानी, बिजली, पंप, फव्वारा, निगरानी कैमरे और खेती से जुड़ी दूसरी सुविधाओं का हवाला दिया गया था। वहीं बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि विनायक घटना के समय खेत में मौजूद नहीं थे।

दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय,जीडीपी ग्रोथ पर बोले...पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार आर्थिक विकास कर रहा भारत

रायपुर,01 सितम्बर 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए अपने दिल्ली दौरे को लेकर उन्होंने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विभागीय समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। समिट में जल संरक्षण, सिंचाई और पेयजल से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में भी जल संरक्षण को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। प्रदेश में किए जा रहे कार्यों की जानकारी समिट में साझा की जाएगी। देश की जीडीपी ग्रोथ को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वैश्विक स्तर पर लगातार अशांति का वातावरण बना हुआ है। इसके बावजूद भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आर्थिक विकास कर रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.8 प्रतिशत रही है।

चिल्फी में ट्रक कंटेनर से 2.23 करोड़ का गांजा पकड़ाया

सीक्रेट चेंबर में छिपाया था,इधर स्कूटी और घर से 21 लाख का माल जब्त

कबीरधाम,01 सितम्बर 2026। कबीरधाम जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी है। 31 अगस्त को एनएच-30 पर वाहनों की जांच के दौरान पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक से 4 क्विंटल 47 किलो 445 ग्राम गांजा बरामद किया। जब्त गांजे की अनुमानित बाजार कीमत 2 करोड़ 23 लाख 75 हजार 250 रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक,गांजे को कंटेनर ट्रक में बनाए गए एक सीक्रेट चेंबर में छिपाकर ले जाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी बलजीत सिंह,निवासी अमृतसर,पंजाब को गिरफ्तार किया है। गांजा परिवहन में इस्तेमाल कंटेनर ट्रक और मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। पुलिस ने गांजे, कंटेनर और मोबाइल फोन समेत कुल 2 करोड़ 50 लाख 80 हजार 250 रुपए का माल जब्त किया है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस गांजा तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। इधर,बस्तर में भी 21 लाख का गांजा पकड़ा गया है। दो मामलों में 56 किलो गांजा जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी ओडिशा से स्कूटी में गांजा ला रहा था,जबकि दूसरे ने इसे जमीन के अंदर छिपाकर रखा था।

चिल्फी थाना के सामने पुलिस ने रोका कंटेनर : पुलिस के अनुसार, 31 अगस्त को चिल्फी थाना के सामने एनएच-30 मेन रोड पर वाहनों की जांच और निगरानी की जा रही थी। इसी दौरान बोडला की ओर से एक संदिग्ध कंटेनर ट्रक आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने कंटेनर को रोककर वाहन में सवार शख्स से पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपना नाम बलजीत सिंह, पट्टी सरा दी गांव चाटीपिंड, थाना चाटीपिंड, जिला अमृतसर, पंजाब बताया। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने कंटेनर ट्रक की तलाशी शुरू की। पुलिस टीम ने कंटेनर रोककर चालक से पूछताछ की।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)